

भारत सरकार की उपेक्षा और दोयम दर्जे के व्यवहार से क्षुब्ध है लद्दाख

लद्दाख को दूसरा कश्मीर बनने पर विवश कर रही मोदी सरकार

दीनबंधु कबीर
लेह, 10 जून।

भारत सरकार की उपेक्षा और दोयम दर्जे के व्यवहार से सम्पूर्ण लद्दाख क्षुब्ध है और भीषण आक्रोश में है। मोदी सरकार की यह उपेक्षा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को दूसरा अस्थिर और अराजक कश्मीर बनने पर विवश कर रही है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लद्दाखियों की समग्र सुरक्षा और संरक्षा पर कतई ध्यान नहीं दे रही है जबकि लद्दाख के गैर-जरूरी मुद्दों को लेकर पतंग उड़ा रही है।

लद्दाख के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत के बाद, केंद्र ने लद्दाख के लिए नई अधिवास और नौकरी आरक्षण नीति की घोषणा की। भूमि, संसाधनों और रोजगार के अवसरों पर नियंत्रण खोने वाले मूल निवासियों ने पिछले पांच वर्षों में लद्दाख में लगातार विरोध प्रदर्शन किया था। स्थानीय निवासियों के लिए अधिकांश सरकारी नौकरियों को आरक्षित करके और लद्दाख का निवासी कौन हो सकता है, इस पर विस्तृत प्रतिबंध लगाकर, नरेंद्र मोदी सरकार ने लद्दाखियों की मांगों को संबोधित करने की कोशिश जरूर की, लेकिन लद्दाख के लोगों का कहना है कि समाधान तक पहुंचने का यह केंद्र सरकार का पहला कदम था। इसके बाद केंद्र ने कदम रोक लिया। लद्दाख के वरिष्ठ नेता और लेह एपेक्स बांडी के

अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने कहा, लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा से जुड़े हमारे दो मुख्य मुद्दे अभी भी लंबित हैं। लेह एपेक्स बांडी उन दो निकायों में से एक है जिन्होंने लद्दाख के लोगों की ओर से केंद्र सरकार के साथ बातचीत की थी। अभी तक उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। दोरजे ने कहा, मुख्य मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। लद्दाखी नेतृत्व ने छठी अनुसूची के रूप में एक संवैधानिक गारंटी मांगी थी, जो देश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए भूमि पर सुरक्षा और नाममात्र की स्वायत्तता की गारंटी देती है। लद्दाख में 97 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की है।

लद्दाख के नेताओं ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए नियमों में लद्दाख में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यह लद्दाख के लिए दुख और अवांछित है। जब नई दिल्ली ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग कर लद्दाख को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया, तो लेह में खुशी की लहर दौड़



गई थी। लेकिन लद्दाख के लोगों ने इस क्षेत्र में अचल संपत्ति के मालिक होने और सरकारी नौकरी पाने के

लद्दाखियों की समग्र सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे मोदी

अपने विशेषाधिकार खो दिए। अगस्त 2021 में, करगिल और लेह दोनों क्षेत्रों ने लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्वीकार करने से इन्कार कर

दिया और पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा। 2022 तक, गैर-स्थानीय लोगों को लद्दाख में जमीन के मालिकाना हक और नौकरी पाने के लिए पात्र होने की बढ़ती चिंता ने लद्दाख के नेतृत्व की चार मांगों को जन्म दिया। ये मांगें थीं, लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपाय, लेह और करगिल जिलों के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटें, लद्दाख के लिए एक भर्ती प्रक्रिया और एक अलग लोक सेवा आयोग की शुरुआत।

केंद्र सरकार के 2 जून के फैसले में आंशिक रूप से उन मांगों को संबोधित किया गया है। नए नियमों के तहत, केवल वही व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश का निवासी होने के योग्य होगा जो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसके गठन के बाद से 15 साल की अवधि के लिए लद्दाख में निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति जिसने 31 अक्टूबर 2019 से सात साल की अवधि के लिए अध्ययन किया है और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक

शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10 या कक्षा 12 की परीक्षा दी है, वह भी निवासी होने के योग्य है। हालांकि, अधिवास नियम केवल लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती में परिभाषित लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के तहत पदों पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए वैध है।

केंद्र ने आरक्षण नीति में संशोधन के लिए एक अध्यादेश भी लाया। इसके अनुसार, लद्दाख में 85 प्रतिशत नौकरियां और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित होंगे। इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण, नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ रहने वालों के लिए 4 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त है। इससे पहले, जम्मू और कश्मीर में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत थी, जिसका लद्दाख एक हिस्सा था। लेह एपेक्स बांडी के नेता दोरजे ने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार ने रोजगार संबंधी असुरक्षाओं को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें और कुछ नहीं है। केंद्र के साथ बातचीत में करगिल जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधि सजाद करगिली डोमिसाइल नीति से असंतुष्ट हैं।

►10पर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया से दो-टूक कहा

आतंकियों के साथ आतंकी ढांचों का खत्म होना जरूरी

नई दिल्ली, 10 जून (एजेंसियां)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों के साथ-साथ आतंकी ढांचों को खत्म करना जरूरी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करना जरूरी हो गया है। यह बात पूरी दुनिया के सामने आ रही है कि पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है कि आतंकवाद को फंडिंग। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को

पाकिस्तान को मिलने वाली विदेशी आर्थिक मदद को बंद करना होगा। आतंकवाद को खाद-पानी नहीं मिलना चाहिए। इसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अहम है, लेकिन उसके निर्णयों पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति में उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह बिल्ली से दूध की रखवाली करवाने वाली बात है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। यह वही पाकिस्तान है, जिसकी जमीन का इस्तेमाल वैश्विक आतंकवाद के लिए होता रहा है। यहां हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी खुले आम घूमते हैं और जहर उगलते हैं। उसे आप वाइस चेयरमैन बनाते हैं। आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी फौज

पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब आतंकवाद को फंडिंग



के अफसर फातिहा पढ़ते नजर आते हैं, यह क्रूर मजाक से कम नहीं है। राजनाथ ने कहा, जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो सैनिकों की सुरक्षा और सरकार की मजबूती दिखाई देती है। इसके साथ एक और शक्ति होती है, स्वतंत्र और स्वतंत्र पत्रकारिता। पत्रकारिता सिर्फ सूचना देने वाली नहीं, बल्कि समाज को सशक्त बनाने वाली और चेतना देने वाली शक्ति होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, उसने देश को झकझोर दिया। उन्होंने धर्म पूछकर मारा, लेकिन हमने उनका धर्म पूछकर नहीं, उनका कर्म देखकर मारा। यह देश की सामाजिक एकता पर हुआ हमला था। धर्म पूछकर मारने के पीछे उनका उद्देश्य

था भारत की सांस्कृतिक एकता को नुकसान पहुंचाना। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने उनके आतंकी ढांचे को तबाह कर दिया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालयों पर पहली बार किसी ने हमला किया है, तो वह भारत है। यह आतंकियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अनुच्छेद 370 पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आप सभी ने देखा होगा कि जब तक जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था, तब तक सभी कहते थे कि कश्मीर भारत में तो है, लेकिन वह भारत से इंटीग्रेट नहीं है। अब 370 हटने के बाद वह भारत से पूरी तरह इंटीग्रेट हो गया है। जम्मू-कश्मीर में लाखों पर्यटक आए। जमीनी स्तर पर वहां सुशासन दिख रहा है। जम्मू-कश्मीर को भारत का मस्तक कहा जाता है, जब यह मस्तक चमकने लगा तो पड़ोसी को चमक बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आतंकी वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों को तो हमने जवाब दे दिया, लेकिन इस तरह की घटना भविष्य में न हो, ►10पर

कमीशन लेकर विदेशों से हथियार खरीदने वाला पुराना भारत

आत्मनिर्भर होकर विश्व को हथियार बेच रहा नया भारत

नई दिल्ली, 10 जून (एजेंसियां)।

कमीशन लेकर विदेशों से हथियार खरीदने वाला पुराना भारत अब नए भारत में तब्दील हो चुका है। आज नया भारत आत्मनिर्भर होकर विश्व को हथियार बेच रहा है। आजादी के बाद से देश के रक्षा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार-नीति 11 साल में समाप्त कर दी गई। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को हथियार निर्यात कर रहा है और विश्व के रक्षा निर्यातक देशों में 25वें स्थान पर पहुंच चुका है। 2025 में भारत ने ब्रह्मास सुपरसोनिक मिसाइल का दूसरी खेप फिलीपींस को भेजी।

देश की सैन्य आत्मनिर्भरता न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है बल्कि बाह्य सुरक्षा की नजरिए से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश का खुद का हथियार बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत हथियारों के मामले में दुनिया के आत्मनिर्भर देशों में शामिल हो गया है। यह परिवर्तन 2014 के बाद होना शुरू हुआ 2014 से पहले भारत का रक्षा निर्यात काफी बहाली के दौर से गुजर रहा था और हम आयात पर निर्भर थे। लेकिन



रक्षा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार-नीति 11 साल में खत्म

इस निर्भरता को आत्मनिर्भरता में बदलने का काम 2014 के बाद आई मोदी सरकार ने किया। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के मुताबिक, 2009 से 2013 तक भारत पूरे दुनिया के हथियारों का 13 प्रतिशत आयात किया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया की सबसे

शक्तिशाली सैन्य क्षमताओं वाला देश हथियारों की आपूर्ति के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर होता चला गया। विदेशी सप्लायर भारत के घरेलू उत्पादन उद्योग को कमजोर करते चले गए। रक्षा निर्यात की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2004-2005 से 2013-14 तक रक्षा निर्यात की कुल राशि 4,312 करोड़ थी जो अब बढ़ कर 23,622 करोड़ हो गई है। रक्षा निर्यात की रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि किस तरह कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को हाथियारे पर रख दिया था। रक्षा निर्यात की रिपोर्ट में

उत्तरी सेवा के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग ने इस रिपोर्ट में बताया है कि 2013-14 तक हमारा निर्यात मात्र 110 मिलियन डॉलर था। हमारे देश के रक्षा निर्यात का कोई अस्तित्व ही नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार, पहले को बढावा मिलेगा। मंत्रालय से एनओसी लेने के बाद व्यापार करने की व्यवस्था थी, उस वक्त भी सरकार ने रक्षा निर्यात पर गंभीरता से विचार नहीं किया। यही कारण है कि 2014 के बाद भी एनडीए सरकार के गंभीर प्रयासों के बावजूद रक्षा निर्यात इतना कम है। ►10पर

कार्टून कॉर्नर



मौसम बेंगलूरु

अधिकतम : 31°
न्यूनतम : 22°

वंदे भारत ट्रेन की सवारी कर भावुक हुए फारूक अब्दुल्ला



जम्मू, 10 जून (व्यूरो)।

वंदे भारत ट्रेन की सवारी कर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अत्यंत भावुक हो गए। फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन से कटड़ा तक वंदे भारत ट्रेन में यात्रा की। उनके साथ उनके दोनों पोते भी थे। उन्होंने कहा, हमें वंदे भारत ट्रेन से बहुत फायदा होगा। हमें खुशी है कि हम इस ट्रेन से कटरा जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा कि ट्रेन

लिंक से कश्मीर के फल व्यापारियों को देश भर के बाजारों तक पहुंच मिलेगी। जब ट्रेन कटड़ा स्टेशन पर पहुंची, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकर्ता फूलों के गुलदस्ते और नारे लगाकर उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए। अब्दुल्ला ने कटड़ा स्टेशन पर उतरते ही कहा, माता ने बुलाया है। आया है बुलावा शेरावाली का। इसी के साथ वहां मौजूद लोगों ने धार्मिक नारे लगाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली हिमालय की पहाड़ियों में अमरनाथ यात्रा के लिए लोग बड़ी संख्या में ट्रेनों से आएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने इस सीधे रेल संपर्क को कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच दिल के रास्ते को जोड़ने की दिशा में एक कदम बताया। श्रीनगर के नौगाम स्टेशन पर चढ़ते समय, जब ट्रेन पहाड़ों और सुरंगों से होते हुए रियासी जिले की शिवालिक पहाड़ियों में चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे ►10पर

लक्षद्वीप के स्कूलों में हिंदी पढ़ने पर रोक लगी

तिरुअनंतपुरम, 10 जून (एजेंसियां)।

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदी पढ़ाए जाने के निर्णय पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने वहां के स्कूली पाठ्यक्रम में अरबी और महल भाषा पढ़ाए जाने को जारी रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में पुराना पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाए और अरबी-महल भाषाएं बच्चों को सिखाई जाती रहें।

केरल हाईकोर्ट ने यह निर्णय अजस अकबर द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह निर्णय लागू करने से पहले कोई सर्वे नहीं किया गया था, इसलिए इस पर रोक लगाई जाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विशेष क्षेत्र में ऐसे निर्णयों के लिए पहले स्थानीय कारकों पर एक सर्वे होना चाहिए।

►10पर

अब कश्मीरियों को चाहिए दिल्ली तक की सीधी ट्रेन



जम्मू, 10 जून (व्यूरो)।

कटड़ा से श्रीनगर तक चलने वाली इतिहासिक वंदे भारत रेल ने कश्मीरियों को खुशी प्रदान की है पर वे इतने से खुश नहीं हैं। कश्मीरियों की मांग है कि जब तक नई दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चालू नहीं होगी कश्मीर की तरक्की नहीं हो पाएगी। कश्मीरियों का मानना है कि ऐतिहासिक रेल लिंक अपने साथ अधिक विश्वसनीयता, सामर्थ्य और पहुंच का वादा लेकर आया है। पर कश्मीरी इसे नकाफी बताते हैं। वे

कहते थे कि इस महत्वाकांक्षी पहल को कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए वास्तव में सार्थक और न्यायसंगत बनाने के लिए, श्रीनगर और नई दिल्ली के बीच एक सीधी, लंबी दूरी की ट्रेन सेवा अगला जरूरी कदम होना चाहिए।

दिल्ली तक की सीधी रेल की मांग के साथ ही उनका कहना है कि अनावश्यक ठहराव या ट्रेन परिवर्तन के बोझ के बिना श्रीनगर-दिल्ली एक्सप्रेस एक गेम-चेंजर होगी। इससे लोगों की आवाजाही आसान होगी, पर्यटकों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल सीधी रेल की मांग सिर्फ यात्रियों की सुविधा के लिए नहीं है। श्रीनगर से एक मजबूत रेल माल ढुलाई प्रणाली को भी वे महत्वपूर्ण बताते थे। वे कहते थे कि क्षेत्र के बागवानी उत्पाद सेब, चेरी, अखरोट, सब्जियां और विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प समर्थ के प्रति संवेदनशील वस्तुएं हैं। ►10पर



जीतो बेंगलूरु नॉर्थ महिला विंग द्वारा जायका प्रतियोगिता का आयोजन

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

जीतो बेंगलूरु नॉर्थ महिला विंग ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस के अंतर्गत राष्ट्रीय योजना हेल्थ एवं न्यूट्रिशन के तहत खान-पान पर आधारित जायका प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता राजाजी नगर स्थित कार्यालय में महिला सदस्यों के लिए आयोजित की गई थी, जिसका नाम जायका - द बॉक्स ऑफ फ्लेवर्स रखा गया। प्रतियोगिता की शुरुआत नवकर महामंत्र से हुई। कार्यक्रम में जीतो नॉर्थ के अध्यक्ष विमल कटारिया एवं महिला विंग कन्वीनर नेमीचंद जैन ने आयोजन के लिए टीम और प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं। प्रतियोगिता की शुरुआत सुबह 9:30 बजे हुई, जिसमें लगभग 20 महिला सदस्यों ने हस्तनिर्मित व्यंजनों की श्रृंखला प्रस्तुत की। प्रतियोगिता तीन प्रकार के व्यंजन (तरल, ठोस) के स्वाद, गुणवत्ता,



प्रस्तुति और सफाई पर आधारित थी। निर्णायक के रूप में हयात सेंट्रिक के अभिमन्यु सिन्हा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से विलुप्त हो चुके व्यंजन सामने आते हैं और पाक प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं का चार दिवारी से बाहर आकर अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करना गर्व का विषय है। दूसरे सत्र सेहत

और जायका में सर्टिफाइड न्यूट्रीशियनिस्ट निमिषा लढ़ा ने सेहतमंद खानपान और न्यूट्रीशियस व्यंजनों की अहमियत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि न्यूट्री शक्ति और पौष्टिक व्यंजन कुपोषण और अधिक वजन दोनों से लड़ने में मदद करते हैं। फिटनेस के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सीजनल खाना खाना, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा

लेना, भरपूर पानी पीना और 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। निर्णायकों द्वारा प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की गई। शीतल बाफना ने प्रथम स्थान, केजल छाजेड़ ने द्वितीय स्थान और सरिता हीरावत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को स्पॉन्सर बर्जरन इंचैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फूलचंद, विमल, सूरज और दीप्ति द्वारा

पुरस्कार और नकद राशि से सम्मानित किया गया। नॉर्थ के महामंत्री विजय सिंघवी ने प्रतियोगिता में विजेताओं को बधाई दी और कहा कि यह महिलाओं की बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का शानदार अवसर है। कार्यक्रम में जीतो महिला विंग एपेक्स श्रमण आरोग्यम कन्वीनर सुनीता गांधी, हाउसहोल्ड मॉडल कन्वीनर बिंदु रायसोनी, जेएलडब्ल्यू बेंगलूरु साउथ अध्यक्ष बबीता रायसोनी, जेएलडब्ल्यू बेंगलूरु नॉर्थ मेंटर सरिता खिवेंसरा, उपाध्यक्ष सुमन सिंघवी, सुमन वेदमूथा सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। संयोजिका लेखा गांधी और सह संयोजिका लता नवलखा ने निर्णायकों का परिचय दिया। सहमंत्री सुमन रांका ने संचालन और मंत्री रक्षा छाजेड़ ने आभार ज्ञापित किया।

सी-आर्म एक्स-रे मशीन अस्पताल को भेंट

हुब्बल्ली/शुभ लाभ ब्यूरो।

एससी शेडर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड हुब्बल्ली के दानदाता विजय शेडर, निखिल शेनर द्वारा हुब्बल्ली नगर निगम के चिटगुप्पी अस्पताल में 22 लाख रुपए की लागत की नई सी-आर्म एक्स-रे मशीन भेंट की गई। इस दौरान आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, विधायक महेश टेंगिकाई, प्रसाद अब्बैया, मेयर रमना बडिगेर, पालिका आयुक्त रूदेश गाली, श्री सिद्धारूढ मठ ट्रस्ट कमेटी के पूर्व चेयरमैन महेन्द्र सिंधी ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि एससी शेडर परिवार के दानदाता विजय शेडर समय समय पर आगे आकर दान देकर जनता की सेवा में अपना योगदान देते हैं। जोशी ने बताया सी-आर्म तकनीक मशीन का उपयोग हड्डियों, जोड़ों और कोमल तत्वों का एक्स-रे करने के लिए किया जाता है। गुदों की पथरी और किडनी स्टोन जैसी समस्याओं के



लिए उच्च गुणवत्ता वाला उपचार प्रदान करने में मदद करने वाली इस मशीन का लाभ आगे से चिटगुप्पी अस्पताल में आने वाले मरीजों को मिलेगी। इस दौरान समाजसेवी महेन्द्र सिंधी ने कहा कि एससी शेडर एंड संस परिवार सदैव दानदाता के रूप में आगे रहता है। इस परिवार ने नवनगर स्थित कैसर हॉस्पिटल को ऑर्पेटिव हॉस्पिटल, महावीर लिंब सेंटर, बिड़नाल और गम्बूर

की सरकारी स्कूल सहित अनेक स्थानों पर 1.25 करोड़ रुपये से अधिक की दान देकर सहयोग किया है। इस दौरान चिटगुप्पी हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीधर दंडप्पनावर ने दानदाताओं का आभार जताया। इस अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद हुब्बल्ली महानगर सेवा प्रमुख सुभाष चंद्रा डंक, हर्ष बाफना, पार्षद राजन्ना कोरवी सहित अन्य उपस्थित थे।

वोक्कालिगा ने कांताराजू रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

राज्य वोक्कालिगा आरक्षण संघर्ष समिति ने मांग की है कि कांताराजू आयोग की रिपोर्ट को खारिज किया जाए और सभी वर्गों के लोगों को न्याय दिया जाए। राज्य वोक्कालिगा आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांतैया, राज्य वोक्कालिगा संघ के पूर्व सचिव एम.ए. आनंद, संघ के महासचिव संपादक नागराज येल-चावाडी, कदाबगेर वोक्कालिगा एक्शन समिति के अध्यक्ष के.सी. शिवरामु, वोक्कालिगा समुदाय के नेता रंगनरसिमहैया, मेलुकोटे शिवराजू और अन्य ने संवाददाता सम्मेलन में बात की। नेताओं ने मांग की कि सरकार को कांताराजू और जे.पी. हेगड़े आयोग की आरक्षण रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि

कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित करने का आदेश दिया है। कर्नाटक राज्य प्रशासनिक परिषद ने अपने आदेश में कर्नाटक सरकार को 9 जजों की पीठ के लिए नियुक्तियों में 56 प्रतिशत आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित करने का आदेश दिया है। इसलिए कर्नाटक राज्य में आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित करना अनिवार्य है। कांताराजू और हेगड़े ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें 75 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी। कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने पहले ही आरक्षण को 50 प्रतिशत तक सीमित करने का आदेश दिया है, इसलिए आरक्षण रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता है। हम मांग



करते हैं कि सरकार इन दोनों की रिपोर्ट को खारिज करे। लगभग सभी समुदायों ने कहा है कि कांताराजू आयोग की रिपोर्ट में गलतियाँ हैं। इसलिए, समिति ने सरकार से संदिग्ध सामाजिक और शैक्षणिक रिपोर्ट को त्यागने और फिर से एक विश्वसनीय सर्वेक्षण करने का आग्रह किया है। कांताराजू और जे.पी. हेगड़े द्वारा किया गया सर्वेक्षण 2014-15 में किया गया था। इसे पहले ही 10 साल हो चुके हैं। कर्नाटक

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार, हर 10 साल में एक सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और उसके आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन यह विडंबना है कि वर्तमान कर्नाटक सरकार कानून को मान्यता दिए बिना कांताराजू और जे.पी. हेगड़े की रिपोर्ट को लागू करने जा रही है। अगर सरकार खुद कानून का पालन नहीं करेगी तो फिर कानून का पालन कौन करेगा।

अब जो सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है, उससे समाज के नागरिकों का विश्वास खत्म हो गया है।

कर्नाटक सरकार ने 2014 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण करने के लिए सूचित किया था। तदनुसार, कांताराजू को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

उक्त आयोग ने 2014-15 में सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण किया था। समाज के कार्यालय को सूचित किया गया था कि सर्वेक्षण करते समय राज्य के सभी नागरिकों की जानकारी एकत्र नहीं की गई थी। उक्त आयोग समय पर सरकार को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा। 2014-2015 में, राज्य की कुल

आबादी के 90 प्रतिशत पर एक सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण किया गया था।

यह काम पूरे पैमाने पर नहीं किया गया है। पिछले 10 वर्षों में राज्य में जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति में भी काफी परिवर्तन आया है।

इस परिप्रेक्ष्य में 10 वर्ष पूर्व की रिपोर्ट को स्वीकार कर निकाले गए निष्कर्ष वास्तविकता से कोसों दूर तथा अप्रासंगिक हैं। सर्वेक्षण में सटीकता बनाए रखने के लिए सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण में ली गई समस्त जानकारी को वेबसाइट पर प्रकाशित करना तथा सभी संघटनों से आने वाली शिकायतों को स्वीकार कर उनमें सुधार करना उचित है।



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को रायचूर में मुपुक्षु दिलीप कुमार जी धोका के दीक्षा निमित्त आयोजित शोभा यात्रा एवं अभिनंदन समारोह में अलसूर संघ का प्रतिनिधित्व किया। संघ मंत्री अभय कुमार बांढिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी एवं मुनि पदमचंद जी के दर्शन कर सुख साता पूछी। यात्रा में वर्षादान का लाभ लिया और अभिनंदन आयोजन में सहभागिता दर्ज की। धनपत राज तातेड़, प्रकाशचंद नाहटा, उगमराज मुथा, मनोज कुमार गांढिया, तेजराज तातेड़ के साथ युवक संघ के सदस्य भी प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित थे।



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। राजस्थान संघ कर्नाटका ट्रस्ट (रजि) बेंगलूरु के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष कैलाश संखलेचा के नेतृत्व में बेंगलूरु पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें शहर के कमिश्नर पद पर मनोनीत किये जाने पर बधाई सहित हार्दिक मंगल शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजस्थान संघ कर्नाटका ट्रस्ट के अध्यक्ष कैलाश संखलेचा, जिनेश मेहता, उगमचंद खांटेड, रूपचंद कुमट, रामलाल गन्ना, भोपाल सोनवाडिया आदि मौजूद थे।

ऋषभ कामधेनु गौशाला में जीवदया एवं वृक्षारोपण के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

मातृछाया जैन महिला संगठन ने सोमनहल्ली, कनकपुरा रोड स्थित ऋषभ कामधेनु गौशाला में जीवदया एवं वृक्षारोपण के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। सदस्याओं ने गायों एवं अन्य पशुओं को चारा, फल, रोटी तथा पक्षियों को दाना खिलाने के साथ ही गौशाला परिसर में आँबला, नीम, तुलसी आदि औषधीय एवं छायादार पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। अध्यक्ष ललिता नागोरी ने कहा कि गौ-सेवा और वृक्षारोपण हमारी संस्कृति की जीवित परंपराएँ हैं। मातृछाया पर्यावरण और करुणा दोनों का सेतु बनकर समाज को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। मार्गदर्शिका त्रिशला कोठारी ने कहा कि अहिंसा केवल शब्द नहीं, जीवनशैली है। जीवों की सेवा कर हम आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज का पौधारोपण आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन-प्राण बनेगा।



उपाध्यक्ष पुष्पा बाफना ने कहा कि गायों और पक्षियों जैसे मासूम जीवों की सेवा में एक अनूठा सुख है, उदारमना दानदाताओं का आर्थिक सहयोग इन प्राणियों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है। मातृछाया ने गौशाला में आर्थिक सहयोग स्वरूप एक विशाल धनराशि का चेक प्रदान किया। संस्थापक हुक्मीचंद जैन ने मातृछाया का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपकी सेवा भावना, समर्पण और करुणा ने आज हमारे गौवंश के लिए पोषण का प्रबंध करने के साथ ही वातावरण को भी समृद्ध किया है। आपका यह योगदान केवल दान

नहीं, बल्कि जीवों के प्रति संवेदना और सेवा का जीवंत उदाहरण है। सचिव रेशमा बडोला ने धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारी एकता और सेवाभाव ही संगठन की शक्ति है, और यही शक्ति हर आयोजन को एक नई ऊँचाई देती है। इस अवसर पर संगठन की पूर्व अध्यक्ष निर्मला दांतेवाडिया, कांता समदड़िया, मनीषा सालेचा, त्रिशला दांतेवाडिया, नीलमा ललवानी, लीला भंसाली, ललीता ए नाग-ठोरी, मीना सोलंकी, उर्मिला सोलंकी, पुष्पा बोहरा, ऊषा चोपड़ा आदि सदस्याएं उपस्थित रहीं।

कांग्रेस ने कर्नाटक में जातिगत आंकड़ों की फिर से गणना करने का किया फैसला

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कर्नाटक में जातिगत आंकड़ों की फिर से गणना करने का फैसला किया है, ताकि कुछ समुदायों की चिंताओं को दूर किया जा सके, जिन्होंने 10 साल पहले किए गए सर्वेक्षण से बाहर रहे जाने की शिकायत की थी। यह निर्णय पार्टी की एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें 4 जून को बेंगलूरु में हुई भगदड़ से निपटने के सरकार के तरीके की भी समीक्षा की गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। जातिगत जनगणना एक बैठक में चर्चा किए गए प्रमुख राज्य मुद्दों में से एक के रूप में उभरी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए, एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुग-पैपाल ने कहा जाति जनगणना पर चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि कर्नाटक सरकार ने जाति जनगणना में जो कुछ भी किया है, उस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति होनी चाहिए। लेकिन जाति की गणना को लेकर कुछ वर्गों और समुदायों में कुछ आशंकाएँ हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक दशक पहले जाति जनगणना



की थी और अब डेटा पुराना हो चुका है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री को 60-80 दिनों के भीतर पुनर्गणना प्रक्रिया करने का सुझाव दिया है। बैठक में हमने जाति जनगणना के बारे में यही निर्णय लिया है।

यह कदम केंद्र द्वारा जाति गणना के साथ राष्ट्रीय जनगणना की अनुसूची की घोषणा के तुरंत बाद उठाया गया है। कांग्रेस नेतृत्व ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें बेंगलूरु में 4 जून को हुई दुखद भगदड़ भी शामिल है, जिसमें चित्रास्वामी स्टैडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान 11 लोगों की जान चली गई थी। वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष ने नेतृत्व को घटना और राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा निश्चित रूप से, हम हर मानव जीवन के बारे में बहुत चिंतित हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कर्नाटक सरकार ने पहले ही यह पता लगाने के लिए न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है कि वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि पार्टी ने चल रही न्यायिक जांच के दौरान बारीकियों में नहीं जाने का फैसला किया, लेकिन वेणुगोपाल ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस का यह स्पष्ट विचार है कि इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से जन-समर्थक रवैया होना चाहिए।

भाजपा को सबसे पहले अपने जघन्य अपराधों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए: प्रियांक खड़गे

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

भगदड़ मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का इस्तीफा मांगने से पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने पलटवार करते हुए भाजपा से कहा है कि वह अपने जघन्य अपराधों की नैतिक जिम्मेदारी ले। महाराष्ट्र में एक पुलिस थाने के सामने भीड़ जमा होने से 5 लोगों की मौत हो गई। कोई भी राष्ट्रीय मीडिया इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। वहां के मुख्यमंत्री और

उपमुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी नहीं दी। उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में भगदड़ में मारे गए लोगों को मुआवजा न देने और इस्तीफा मांगने पर कोर्ट ने भाजपा को फटकार लगाई है। कुंभ मेले में भगदड़ में कार्यक्रम आयोजित करने और उसमें सफलता पाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत किसी और ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने भाजपा को फटकार



लगाते हुए कहा ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद हम किस मुह से अपनी सरकार का इस्तीफा मांगते हैं? मंगलूरु में सुहास शेठ्टी हत्याकांड की एनआईए द्वारा जांच

करने के पीछे एक राजनीतिक मकसद है। शव पर राजनीति करना भाजपा की बुरी आदत है। पहले भी उन्होंने पारा मेस्ता की मोते के मामले को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर सार्वजनिक शांति को नष्ट किया था। उस समय राज्य पुलिस की रिपोर्ट पर भी संदेह किया गया था। आखिरकार सीबीआई जांच ने भी राज्य पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने पूछा कि भाजपा की शोभा करंदलाजे

या किसी अन्य सांसद ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मंत्री भगदड़ के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को तोड़-मरोड़ कर भाजपा गलत सूचना फैला रही है। बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने में वे माहिर हैं, चित्रास्वामी स्टैडियम में आयोजित कार्यक्रम सरकार का नहीं था। निजी संस्था के पत्र के आधार पर स्टॉफ उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा कहने में

मुख्यमंत्री की क्या गलती है? मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति और भगदड़ मामले समेत कई मुद्दों पर आलाकमान से चर्चा करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि केपीसीसी अध्यक्ष को बदलने और मंत्रिमंडल में फेरबदल की अफवाह कहाँ से उड़ी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जिम्मेदार और परिपक्व है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा की तरह डर कर भागेंगे नहीं।

फिलहाल कैबिनेट फेरबदल पर कोई चर्चा नहीं: सतीश जारकीहोली

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल मंत्रिमंडल में फेरबदल पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री

है। इसलिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आए हैं। वे दोनों



सिद्धरामैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार आलाकमान के नेताओं से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि भगदड़ मामले में किसकी विफलता और कौन दोषी है, यह निर्धारित करने के लिए सरकार जांच रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि 15 दिन या एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सरकार के हाथ में होगी। उन्होंने कहा यह कहना सही नहीं है कि इस घटना को लेकर समन्वय की कमी है। यह एक घटना है। वे इसे ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

आलाकमान के नेताओं से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि भगदड़ मामले में किसकी विफलता और कौन दोषी है, यह निर्धारित करने के लिए सरकार जांच रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई करेगी। उम्मीद है कि 15 दिन या एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सरकार के हाथ में होगी। उन्होंने कहा यह कहना सही नहीं है कि इस घटना को लेकर समन्वय की कमी है। यह एक घटना है। वे इसे ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

जो मुडा अधिकारियों सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए मुखौटा/डमी हैं। 9 जून तक, साइटों का बाजार मूल्य 100 करोड़ है। इससे पहले जनवरी में, ईडी ने लगभग 300 करोड़ के बाजार मूल्य वाले 160 मुडा साइटों को अस्थायी रूप से जब्त किया था, जिनमें से अधिकांश रियल एस्टेट एजेंटों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थे। इसके साथ ही अस्थायी रूप से जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 400 करोड़ हो गया है। हालांकि यह मामला कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बी.एम. को आवंटित 14 वैकल्पिक स्थलों से संबंधित है, जिनमें ईडी को खामियां मिली हैं, लेकिन ईडी ने उन स्थलों को जब्त नहीं किया है, क्योंकि पार्वती ने उन्हें मुडा को वापस कर दिया है। मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार ईडी की जांच में विभिन्न कानूनों और सरकारी आदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और अन्य धोखाधड़ी के तरीकों से मुडा साइटों के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला समझे आया है। जी. टी. दिनेश कुमार सहित पूर्व मुडा आयुक्तों की भूमिका अयोग्य संस्थाओं/व्यक्तियों को मुआवजा साइटों के अवैध आवंटन में सहायक के रूप में सामने आई है। जांच के दौरान नकदी, बैंक हस्तांतरण, चल/अचल संपत्तियों के रूप में अवैध आवंटन करने के लिए रिश्त प्रप्त करने के संबंध में साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। अवैध आवंटन करने के तौर-तरीकों में अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करना और सरकारी आदेशों का सीधा उल्लंघन करते हुए नकली दस्तावेजों/अधूरे दस्तावेजों का उपयोग करके आवंटन करना और कुल्लु-मामलों में आवंटन पत्रों की पिछली तारीख भी शामिल थी। इन अवैध आवंटनों को करने के लिए प्राप्त रिश्त को एक सहकारी समिति और आवंटन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के रिश्तेदारों/सहयोगियों के बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था। इस प्रकार प्राण धनराशि का उपयोग मुडा अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम पर अवैध रूप से आवंटित मुडा साइटों में से कुछ को खरीदने के लिए किया गया।

लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसमें कहा गया कि लंबित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है, मामले में दिए गए किसी भी बयान का इस्तेमाल आरोपी द्वारा किया जा रहा है। स्वप्रेषणा से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी ने सुनवाई की। विधान परिषद के एक पूर्व सदस्य ने याचिका में पक्षकार बनने की मांग की। इस बीच, एक वकील ने बताया कि वह भगदड़ के संघर्ष में एक जनहित याचिका (पीआईएल) भी दायर कर रहे हैं। 5 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टैडियम में हुई भगदड़ की घटना का स्वतः सत्राज्य लिया था और राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।



आरसीबी विजय भगदड़ मामला

13 जून को बेंगलूरु में सरकार के खिलाफ करेंगे व्यापक विरोध प्रदर्शन: विजयेंद्र

शिवमोग्गा/शुभ लाभ ब्यूरो।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने घोषणा की है कि जनविरोधी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार के खिलाफ व्यापक संघर्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जनविरोधी कांग्रेस सरकार को हटाए जाने तक संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है। 13 जून को बेंगलूरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता, घटना के पीड़ितों के परिवार के सदस्य और प्रभावित लोग आएंगे।

उन्होंने बताया कि करीब 15-20 हजार प्रदर्शनकारी शामिल होंगे। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की घटना में आरसीबी आरोपी नंबर 1 नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप 11 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री आर-पेपी नंबर 1 हैं, उपमुख्यमंत्री दूसरे आरोपी हैं, गृह मंत्री परमेश्वर, जो



हथ बांधकर बैठे थे, वे आरोपी नंबर 3 हैं। अगले जिम्मेदार पक्ष आरसीबी, केएसीए, डीएनए हैं। भाजपा ने मांग की थी कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के ऑन-ड्यूटी जज करें। उन्होंने इसे जांच के लिए सीआईडी को दे दिया। दूसरी ओर, उन्होंने जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों से कराने का आदेश दिया है। उन्होंने उन पर जिसे चाहें नियुक्त करने और राज्य सरकार को क्लीन चिट देने और अधिकारियों को दोषी ठहराने

और जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। विजयेंद्र ने मांग की कि अगर राज्य सरकार में थोड़ी भी गरिमा है, तो हाईकोर्ट के मौजूदा जजों को इस मामले की जांच करनी चाहिए। सीएम और डीसीएम के बीच प्रतिस्पर्धा थी। मुख्यमंत्री ने अपनी लोकप्रियता के लिए विधान सौधा के सामने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। जबकि डीके शिवकुमार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया

था। उनके भ्रम का शिकार कौन हुआ? किसकी इज्जत चली गई? वे चिन्नास्वामी स्टेडियम मामले में जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को यह बयान देना चाहिए कि सरकार का सीएम और डीसीएम के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने राज्य के सम्मान को भी बर्बाद किया है। वे सेल्फी और लोकप्रियता के आदी थे। उन्होंने राज्यपाल को गलत रास्ते पर खींच लिया और उन्हें भी बैठा दिया। क्या हमने

विधानसभा में कार्यक्रम के लिए कहा था? हमने जुलूस की अनुमति मांगी थी। अगर हम मार्च करते, तो शायद यह त्रासदी नहीं होती। हमने प्रशंसकों की ओर से आह्वान किया है। हालांकि, उन्होंने पूछा कि क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है। क्या कानून और व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह विपक्ष की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के लोगों की भावनाओं को राज्य के मुख्यमंत्रियों तक पहुंचाने के इरादे से आज सीएम को एक खुला पत्र लिखा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने पत्र इसलिए लिखा था ताकि सीएम, डीसीएम और राज्य सरकार उन लोगों के परिवारों की भावनाओं को समझे जिन्होंने अपनी जान गंवाई और प्रभावित हुए। मुझे विश्वास नहीं है कि मुख्यमंत्री पत्र देखने के बाद जवाब देंगे। राज्य सरकार मोटी चमड़ी वाली है।



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) ने ट्रेन संख्या 16595/596 केएसआर बेंगलूरु-कारवार पंचगंगा एक्सप्रेस में पांच अतिरिक्त कोच अस्थायी आधार पर जोड़ने का फैसला किया है, ताकि पांच महीने तक सेक्टर पर दिन में ट्रेन सेवाएं रद्द होने के कारण होने वाली कमी को पूरा किया जा सके। पंचगंगा एक्सप्रेस 14 एलएचबी कोचों के साथ चलती है। दपरे 11 जून से बेंगलूरु-एंड से और 12 जून से कारवार-एंड से दो 3-टियर एसी इकॉनमी, दो सामान्य द्वितीय श्रेणी और एक स्लीपर क्लास कोच जोड़ेगा, जिससे कुल 19 कोच हो जाएंगे।

यह निर्णय उडुपी-चिक्कमगलूरु के सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी और कुमता के विधायक दिनाकर शेड्डी द्वारा कारवार और बेंगलूरु के बीच अतिरिक्त रात्रि सेवा की मांग के बाद लिया गया है, क्योंकि दिन में बारिश के कारण ट्रेन रद्द रहती है। दपरे ने सकलेशपुर-सुब्रमण्य रोड घाट सेक्शन पर विद्युतीकरण कार्य की सुविधा के लिए 31 मई से 154 दिनों के

लिए ट्रेन संख्या 16575/576 और 16539/540 यशवंतपुर-मंगलूरु जंक्शन त्रि-सप्ताहिक गोमतेश्वर एक्सप्रेस और साप्ताहिक, तथा ट्रेन संख्या 16515/516 यशवंतपुर-कारवार त्रि-सप्ताहिक एक्सप्रेस सेवाओं को रद्द कर दिया था। कुंडापुरा और उत्तर कन्नड़ के यात्री संघों ने कहा है कि दपरे ने समय सारिणी को प्रभावित किए बिना पंचगंगा में और कोच जोड़ने की उनकी मांग पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोच बढ़ाने से लगभग 400 सीटें बढ़ेंगी। यह कहते हुए कि शाम 6.50 बजे बेंगलूरु से रवाना होकर सुबह 8.25 बजे कारवार पहुंचना और शाम 6 बजे कारवार से रवाना होकर सुबह 7 बजे बेंगलूरु पहुंचना, पंचगंगा एक्सप्रेस के तट पर सबसे ज्यादा मांग वाली सेवा बनने का कारण है, यात्री संघों ने

रेलवे से आग्रह किया है कि कोचों की संख्या में वृद्धि से समय सारिणी प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। कोच की संख्या में वृद्धि के बाद ट्रेन 16595/596 की क्रॉसिंग सुब्रह्मण्य रोड स्टेशन पर होगी, क्योंकि घाट सेक्शन पर सिरिबागिलु स्टेशन, जहाँ वर्तमान में ट्रेनें गुजरती हैं, 15 से ज्यादा कोच वाली ट्रेनों को समायोजित नहीं कर सकता। यात्री नहीं चाहते कि क्रॉसिंग में बदलाव की वजह से कारवार-बेंगलूरु ट्रेनों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो। इसी तरह, दक्षिण कन्नड़ के यात्रियों ने मांग की है कि बदली हुई क्रॉसिंग की वजह से केएसआर बेंगलूरु-कन्नूर (ट्रेन 16511) ओवरनाइट एक्सप्रेस के चलने पर असर नहीं पड़ना चाहिए। संरक्षक जी. कार्तिक कामथ ने कहा कि दक्षिण पश्चिम रेलवे को दिन की ट्रेनों के रद्द होने की समस्या से निपटने के लिए ट्रेन संख्या 16585/586 एसएमवीटी बेंगलूरु-मुदेंश्वर-एसएमवीटी बेंगलूरु और 16511/512 केएसआर बेंगलूरु-कन्नूर में भी कोचों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

कांग्रेस का कोई हाईकमान नहीं खोखली कमान है: अशोक

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने चेतावनी दी है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी भगदड़ की घटना के सिलसिले में यदि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का इस्तीफा नहीं लिया गया तो कांग्रेस आलाकमान के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने हाल ही में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में मारे गए दाशरहल्ली के एम.एस. रामैया लेआउट निवासी भूमिक के घर जाकर उनके माता-पिता को संवेदना व्यक्त करने के बाद संवाददाताओं से बात की। इस मामले में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोषी हैं। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एआईसीसी नेताओं को सिद्धरामैया और डी.के. शिवकुमार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आलाकमान परेशान होगा। सीएम बार-बार झूठ बोल रहे हैं। जब भी कोई उन्हें बुलाता है, तो वे कहते हैं कि वे चले गए हैं। डीसीपी ने रिपोर्ट दी है कि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कर्मचारियों की कमी है। पीडब्ल्यूटी ने आदेश दिया है कि 25 लोग होने चाहिए। डीपीआर नोट मिलने के बाद वह सीएस के पास जाता है। वह पत्र लिखकर सीएम को भेजते हैं। सीएम कार्यक्रम करने की अनुमति देते हैं। अगर आपने अनुमति नहीं दी है तो आप

उस फाइल को रिलीज कर दें। अगर आपने अनुमति नहीं दी है तो डीपीआर सचिव को स्पेंड करें। सीएम गैरजिम्मेदाराना तरीके से कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। अगर सीएम द्वारा साइन की गई फाइल रिलीज होती है तो क्या सरकार को नुकसान होगा? अगर आपने जिस फाइल पर साइन किया है उसे सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो बिना अनुमति के कार्यक्रम करने वाले अधिकारियों को स्पेंड करें। मौत की खबर दोपहर 3.15 बजे आई। आपके मीडिया सलाहकार, आपके स्टाफ की नाकामी साफ दिख रही है। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि वे जानते हुए भी कार्यक्रम कर रहे थे। इस मुद्दे को छिपाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा उठाया गया है।



कांग्रेस को छल-कपट का शिकार नहीं होना चाहिए। सीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सीएम और डीसीएम को बदला जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें नहीं बदला गया तो जनता कांग्रेस सरकार को बदल देगी।

मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए हैं। दिल्लीवासी भी भ्रमित हैं। आलाकमान भी इसे लेकर भ्रमित है। राज्य सरकार के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया गया है, जिसका मतलब है कि यह सरकार का अपमान है। अशोक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवार कह रहे हैं कि यह सरकार की गलती है।

पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग

मंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर हिंदू नेताओं को निशाना बनाने के लिए पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। यहां भाजपा जिला कार्यालय में बोलते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि बाजपे में सुहास शेड्डी की हत्या के बाद हिंदू कार्यकर्ताओं को परेशान करके कांग्रेस सरकार गुंडा व्यवहार कर रही है।

विजयेंद्र ने आरोप लगाया, सुहास शेड्डी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के बजाय, कांग्रेस सरकार आधी रात को हिंदू नेताओं के घरों पर छापेमारी करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। यह किसी धमकी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए



हिंदू नेताओं, विभिन्न संगठनों के सदस्यों, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और शहर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा हम विशेष व्यवहार की मांग नहीं कर रहे हैं। हमने केवल इतना कहा है कि अधिकारी सरकार के दबाव में काम न करें और हिंदू नेताओं को धमकाना बंद करें। भाजपा प्रमुख ने दावा किया कि राज्य में सांप्रदायिकता विरोधी विंग के गठन के बाद हिंदू नेताओं पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया यह टास्क फोर्स हिंदू नेत-1ओं के खिलाफ साजिश रचने और उनमें डर पैदा करने का एक साधन मात्र है, खासकर भाजपा

के गढ़ों में। विजयेंद्र ने सुहास शेड्डी मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि भाजपा की पिछली मांग के बावजूद राज्य सरकार ने ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भाजपा और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के खिलाफ जानबूझकर अपने नेत-1ओं को बचाने का आरोप लगाया। डॉ प्रभाकर भट जैसे हिंदू नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन जब इवान डिस्जूजा जैसे लोग प्रधानमंत्री और राज्यपाल के खिलाफ बोलते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती।

उन्होंने कहा कर्नाटक में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राजनीतिक नेतृत्व के विफल होने पर पुलिस अधिकारियों को मनमाने ढंग से स्थानांतरित किया जा रहा है, जैसा कि दक्षिण कन्नड़ और बेंगलूरु में देखा गया है। लव जिहाद, मवेशी चोरी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध रेत खनन जैसी गंभीर चिंताओं का जिक्र करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि इन मुद्दों को पहले संबोधित किया जाना चाहिए। अगर इन पर अंकुश लगाया जाता है, तो हमारे नेताओं को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं होगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, जो

भी मौजूद थे, ने आरोप लगाया कि राज्य के पुलिस स्टेशन कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों की तरह काम कर रहे हैं। देशद्रोहियों और देशभक्तों के साथ व्यवहार करने में कोई अंतर नहीं है। दोनों के लिए कानून एक जैसा नहीं हो सकता। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अशोक ने हिंदू नेताओं को भाजपा के समर्थन की पुष्टि की और उनसे डरने की अपील नहीं की। सुहास शेड्डी की कथित उपद्रवी शीट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा उपद्रवी शब्द की अलग-अलग परिभाषाएं हैं। यहां तक कि डी के शिवकुमार और राहुल गांधी जैसे नेताओं के खिलाफ भी मामले हैं। अदालत को फैसला करने दें। उन्होंने पुलिस से रहमान की हत्या के पीछे के मकसद की जांच करने का भी आग्रह किया और स्पष्ट किया कि यह सांप्रदायिक घटना नहीं थी। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी भी शामिल थे।

राज्य के विभिन्न जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

राज्य में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। रविवार तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है और दक्षिणी आंतरिक जिलों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। राज्य में पिछले तीन-चार दिनों से बारिश शुरू हो गई है और दिन-प्रतिदिन बारिश बढ़ने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में मेलई चक्रवात के प्रभाव और आंतरिक इलाकों में ट्रेप के कारण आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और शाम और रात में बारिश हो रही है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र की जानकारी के अनुसार सोमवार को उडुपी जिले में व्यापक बारिश हुई। धारवाड़ तालुक के नवलगुंडा में 118.2 मिमी भारी बारिश हुई।



बीदर, दावाणगेरे, कलबुर्गी, दक्षिण कन्नड़ और बेंगलूरु शहरी जिलों में मध्यम व्यापक बारिश हुई। तुमकुरु, मांड्या, रामनगर, गदग, बेंगलूरु ग्रामीण, उत्तर कन्नड़, चिक्कबल्लापुर और चित्रदुर्ग जिलों में छिटपुट बारिश हुई। धारवाड़, बेलगावी, शिवमोग्गा, रायचूर, हावेरी, विजयनगर, कोदग, विजयपुरा, कोडगु, याल्हागी, मैसूर, बागलकोट, बल्लारी, चिक्कमगलूर, कोप्पल, चामराजनगर, हासन जिलों में कुछ स्थानों पर ही बारिश हुई।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य में सामान्य मानसून जारी रहेगा। बारिश में और वृद्धि होगी। दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में व्यापक वर्षा की संभावना है। उत्तर कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक, तटीय और मलनाड जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। राज्य के पूर्वी जिलों में बारिश बढ़ेगी। गुरुवार से बारिश बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर भारी बारिश के संकेत हैं। अगले रविवार तक राज्य में और अधिक बारिश का अनुमान है।

कर्नाटक के मुजराई मंदिरों में 15 अगस्त से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध: मंत्री

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने घोषणा की कि 15 अगस्त से राज्य भर में मुजराई विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंदिरों में पानी की बोतलों सहित सभी प्रकार के प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। विकास सौधा में आयोजित मुजराई विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से सभी मंदिरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति में इन मंदिरों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए आदेश को लागू करने के लिए दो महीने की अवधि दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरान पहले से खरीदी गई प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन 15 अगस्त से मंदिर परिसर में उनका उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।



स्मार्ट सिटी के दावों के बीच नंथूर के पास उपेक्षित पेड़, कचरा से सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी

मंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

नंथूर ऑटो स्टैंड के पास एक खतरनाक तरीके से लटका हुआ पेड़ एक सप्ताह से अधिक समय से गंभीर खतरा पैदा कर रहा है, जिससे मंगलूरु सिटी कार्पोरेशन (एमसीसी) की प्रतिक्रिया की तत्परता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अधिकारी गिरे हुए पेड़ को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले किसी दुर्घटना या जान जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा, मंगलूरु के एक प्रमुख स्थान नंथूर पुलिस चौकी के पास कूड़े के ढेर और गैस पाइप को लापरवाही से सड़क किनारे की नालियों में फेंक दिया गया है। यह लंबे समय से एक लगातार समस्या बनी हुई है, फिर भी न तो स्थानीय प्रतिनिधियों और न ही अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया है। भारी बारिश और तेज



हवाओं के दौरान, अवरूद्ध नालियों के कारण सड़कों पर पानी बह जाता है, जिससे लोगों को गंभीर असुविधा होती है। समस्या इतनी स्पष्ट होने के बावजूद, जिम्मेदार लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। यह स्थिति शहर के स्मार्ट सिटी बनने की आकांक्षाओं पर संदेह पैदा करती है। निवासियों का दावा है कि अधिकारी और योजनाकार भले ही स्मार्ट छवि बनाने का लक्ष्य बना रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कूड़े के

ढेर और असुरक्षित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से भरी हुई है। स्थानीय लोगों ने आगे कहा कि अगर नगर निगम ने ऐसे बुनियादी मुद्दों को हल करने के लिए उपाय किए होते, तो नालियों की ओवरफ्लो होने और लोगों की परेशानियों से बचा जा सकता था। अब वे अधिकारियों से किसी भी संभावित दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।

संघर्ष के मूल कारण यथावत बने हुए हैं, भारत ने दी पाकिस्तान को चेतावनी

ब्रुसेल्स, 10 जून (एजेंसियां)

भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई आपरेशन सिन्दूर के लगभग तीन सप्ताह बाद पुनः चेतावनी दी है कि संघर्ष के मूल कारण अब भी यथावत बने हुए हैं और आगे कभी भी आतंकवादी हमलों से उकसाए जाने पर भारत पाकिस्तान में कहीं भी और किसी भी हद तक हमला करने के लिए तत्पर है।

विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने ब्रुसेल्स की यात्रा के दौरान बेल्जियम के समाचारपत्र पोलिटिको के साथ एक साक्षात्कार में कहा, यह (पाकिस्तान) एक ऐसा देश है जो राज्य की नीति के साधन के रूप में आतंकवाद के उपयोग में पूरी तरह से लिप्त है। यही पूरा मुद्दा है।

यह पूछे जाने पर कि क्या पिछले महीने युद्ध शुरू होने की परिस्थितियाँ अभी भी हैं, उन्होंने कहा, यदि आप आतंकवाद के प्रति प्रतिबद्धता को तनाव का मूल कारण कहते हैं, तो बिल्कुल, यह है।

दस मई को सैन्य कार्रवाई रोकने के बाद से एक भारतीय अधिकारी द्वारा भारतीय पक्ष को हुए नुकसान के बारे में उन्होंने कहा कि भारत के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने पाकिस्तानी वायु सेना को इसके विपरीत कहीं अधिक व्यापक नुकसान पहुंचाया है, जिससे पाकिस्तान को शांति के लिए गुहार लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, जहां तक मेरा संबंध है,



राफेल कितना प्रभावी था या अन्य प्रणालियां कितनी प्रभावी थीं – स्पष्ट रूप से, मेरे लिए प्रसन्नता का सबूत पाकिस्तानी पक्ष में नष्ट और अक्षम हवाई क्षेत्र हैं।

विदेश मंत्री ने कहा, लड़ाई 10 तारीख को एक कारण से और केवल एक कारण से बंद हुई, जो यह था कि 10 तारीख की सुबह हमने इन आठ पाकिस्तानी, मुख्य आठ पाकिस्तानी हवाई क्षेत्रों पर प्रहार किया और उन्हें अक्षम कर दिया। और इसके लिए मेरी बात पर यकीन नहीं करें, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो गूगल में उपलब्ध हैं। आप उन रनवे और उन हैंगरों को देख सकते हैं जिन्हें नष्ट किया गया है।

डॉ जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान 'हजारों' आतंकवादियों को 'खुले में' प्रशिक्षित कर रहा है और उन्हें अपने

दक्षिणी पड़ोसी देश में भेज रहा है। उन्होंने कहा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उनके लिए हमारा संदेश यह है कि यदि आप अप्रैल में किए गए बर्बर कृत्यों को जारी रखते हैं, तो प्रतिशोध होने वाला है, और यह प्रतिशोध आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी नेतृत्व के खिलाफ होगा। और हमें परवाह नहीं है कि वे कहाँ हैं। अगर वे पाकिस्तान में बहुत अंदर गहराई में हैं, तो हम पाकिस्तान में उस गहराई तक जाएंगे।

यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थ के रूप में खुद को स्थापित करके अपना कद बढ़ाने की भारत की कोशिश के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमने कभी भी अपने लिए कोई भूमिका नहीं मांगी या दावा नहीं किया। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं

तो हम तैयार हैं, लेकिन हम खुद पर दबाव नहीं डाल रहे हैं।

डॉ जयशंकर ने कहा, भारत ने दोनों पक्षों के साथ एक खुली रेखा रखी है, और कभी-कभी संदेश एक दूसरे को पहुंचाए हैं। जब यूक्रेन के प्रधानमंत्री ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा के बारे में मास्को को जानकारी देना चाहते थे, तब उनके बीच एक माध्यम के रूप में कार्य किया था।

भारत के रक्षा उद्योग के बारे में चर्चा करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा, भारत अपने स्वयं के 'मेड इन इंडिया' रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।

उनमें से कुछ का पाकिस्तान के साथ हाल के संघर्ष में परीक्षण हुआ है और ये 'बहुत सिद्ध' और 'बहुत सफल' रहे हैं। इसलिए जबकि भारतीय कंपनियां यूरोप के साथ अधिक काम करना चाहती हैं, मैं इसे केवल यूरोप से अधिक हथियार खरीदने के रूप में नहीं देखता।

दोनों पक्षों के बीच तेजी से, डिजाइन पर सहयोग हो रहा है। हम अब बहुत कम शुद्ध खरीदारी करते हैं।

भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बारे में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोप साल के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने की राह पर हैं, लेकिन यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र और मूल नियम मतभेद के प्रमुख बिंदु बने हुए हैं।

भारत में प्रजनन संबंधी समस्या गंभीर रूप ले रही है: यूएनएफपीए

नई दिल्ली 10 जून (एजेंसियां)।

भारत की जनसंख्या में 36 प्रतिशत यानी हर तीन में से एक वयस्क अनचाहे गर्भ से परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ लगभग 30 प्रतिशत ऐसे लोग भी हैं जिनके लिये मातृत्व सपना ही बनकर रह जाता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की 'विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025' की आज यहां जारी एक रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में यह कटु सत्य सामने आया है।

यूएनएफपीए की कार्यकारी निदेशक डॉ नतालिया कानेम ने वर्चुअल मीडिया संगोष्ठी में यह रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि ज्यादातर लोग अपनी पसंद के मुताबिक 'परिवारों' का गठन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, यह गर्भधारण में आने वाली पेशानियों से जुड़ा है, जिसका जवाब लोगों की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ा है। इसमें परिवार के लिए भुगतान वाली छुट्टी, किफायती प्रजनन संबंधी देखभाल और सहायक साथी का होना शामिल है।

'वास्तविक प्रजनन संकट: बदलती वैश्विक परिस्थितियों में प्रजनन एजेंसी की खोज' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में दृष्टिकोण में बदलाव पर जोर दिया गया है, जिसे जन्म दर में गिरावट के बारे में चिंताओं से लोगों का ध्यान हटाकर प्रजनन लक्ष्यों और उसे प्राप्त करने की उनकी क्षमता के



रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय असुरक्षा ही वांछित परिवार के सदस्यों की संख्या में सबसे आम बाधा है। लगभग 40 प्रतिशत लोग वित्तीय सीमाओं का हवाला देते हैं, उसके बाद नौकरी

की असुरक्षा (21 प्रतिशत), अपर्याप्त आवास (22 प्रतिशत), और बच्चों की देखभाल संबंधी सुविधाओं की कमी (18 प्रतिशत)। सामान्य खराब स्वास्थ्य (15 प्रतिशत), बांझपन (13 प्रतिशत) और सीमित मातृ स्वास्थ्य सेवा (14 प्रतिशत) जैसी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी इस बाबत भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, भविष्य के बारे में जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चिंतायें लोगों को बच्चे पैदा करने से हतोत्साहित कर रही हैं।

रिपोर्ट में एक बयान के हवाले से कहा गया है कि पाँच में से लगभग एक व्यक्ति ने यह भी कहा है कि उन्हें परिवार या अन्य लोगों से कम बच्चे पैदा करने का दबाव महसूस होता है।

इस बीच, यूएनएफपीए की भारत स्थित प्रतिनिधि एंड्रिया एम. वोजनार ने कहा, भारत में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है जिसका अर्थ है कि आज लाखों और मातायें जीवित हैं। बच्चों की परवरिश कर रही हैं और समुदायों का निर्माण कर रही हैं। फिर भी, राज्यों, जातियों और आय समूहों में गहरी असमानताएँ बनी हुई हैं।

देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या सात हजार के करीब

नई दिल्ली 10 जून (एजेंसियां)।

देशभर में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या मंगलवार सुबह तक 6815 पहुंच गयी और पिछले 24 घंटों के दौरान इसके संक्रमण से तीन और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 68 पहुंच गयी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज सुबह आठ बजे तक 324 नए संक्रमण के मामले सामने आए, जिससे कुल सक्रिय मामलों की संख्या 6,815 हो गई और इस बीमारी के संक्रमण से 7644 मरीज स्वस्थ हो गये हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से तीन और मरीजों की जान जाने से मृतकों की संख्या 68 हो गयी है। इस अवधि में राष्ट्रीय राजधानी, केरल और झारखंड से एक-एक मरीज की मौत हुई है।

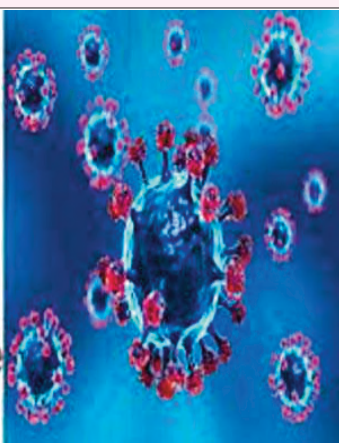
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। देश में 30 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में कोरोना सक्रिय मामलों



में वृद्धि हुई है। जिनमें से केरल, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

कोरोना संक्रमण के मामले में केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां आज सुबह तक 96 सक्रिय मामले बढ़ने के साथ इसका आंकड़ा दो हजार पार कर 2053 तक पहुंच गया और दिल्ली में लगभग 37 मामलों के घटने से संक्रमितों की कुल संख्या 691 रह गई।

इसके अलावा गुजरात में 1109, पश्चिम बंगाल में 747, महाराष्ट्र में 613, कर्नाटक में 559, तमिलनाडु में 207, उत्तर



नए सब-वेरिएंट जैसे कि जेएन.1, एनबी.1.8.1, एलएफ.7 और एक्सएफसी के कारण हैं। इनमें संक्रमण की संभावना अधिक है, लेकिन इनमें लक्षण हल्के हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन्हें वर्तमान में निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है – अभी तक चिंता का विषय नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने

की आवश्यकता है। इस बीच, कोरान के लिए जिम्मेदार वायरस सार्स-सीओवी-2 खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह अब अप्रत्याशित आपातकाल की तरह व्यवहार नहीं करता है – बल्कि, यह पलू की तरह बीमारियों के आवर्ती चक्र का हिस्सा बन गया है।

कोरोना के मामलों में वृद्धि के जवाब में, केंद्र सरकार ने अस्पतालों की तैयारी और ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न राज्यों में मांक ड्रिल शुरू की है।

सेना ने कैप्टन विजयंत थापर सहित 65 शूरवीरों के परिजनों को सम्मानित किया

नई दिल्ली 10 जून (एजेंसियां)।

सेना ने 26वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत इस लड़ाई के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले योद्धाओं के परिजनों को सम्मानित करने की कड़ी में मंगलवार को कैप्टन विजयंत थापर (वीर चक्र) सहित 65 शूरवीरों के परिजनों को उनके घर जाकर सम्मानित किया।

सेना ने बताया है कि कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर सेना सर्वोच्च बलिदान देने वाले योद्धाओं के घर-घर जाकर वीर सैनिकों के परिजनों तथा देशवासियों को भारत मां के इन वीर सपूतों के अदम्य साहस और उनके शौर्य की पराकाष्ठा के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही सेना सभी वीर सेनानियों के घर जाकर सम्मानपूर्वक स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्हें सम्मानित कर रही है।

सेना के अधिकारियों का एक दल कैप्टन थापर के नोएडा स्थित आवास पर पहुंचा और उनके माता पिता से मुलाकात कर उन्हें आभार पत्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सेना के अधिकारी इसके अलावा यहां



राजधानी दिल्ली में वीर चक्र से सम्मानित राइफलमैन अनसुया प्रसाद की पत्नी, जयपुर में हवलदार बस्ती राम की पत्नी, कुरुक्षेत्र में लांस नायक गुरमेल सिंह के माता पिता, राजस्थान के वैशाली नगर में नायक आनंद सिंह की पत्नी और देहरादून में सेना पदक से सम्मानित हवलदार हरिओम के परिजनों सहित 60 से अधिक योद्धाओं के परिजनों से मिले और उन्हें सम्मानित किया।

इस अवसर पर सेना की ओर से यह भावना भी व्यक्त की जा रही है कि वह अपने वीर साथियों को कभी नहीं भूलती और न कभी भूलेगी। सेना का कहना है, यह

हमारा कर्तव्य और हमारी भावना है कि हम उनके परिजनों को बताएं कि हमारे वीर सेनानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। हमारे वीर बलिदानियों का परिवार अकेला नहीं है, भारतीय सेना उसका परिवार है और पूरी भारतीय सेना हमेशा उनके साथ खड़ी है।

सेना का यह कदम शूरवीरों को सम्मान देने के साथ-साथ यह भी बताता है कि देश अपने वीर बलिदानियों को कभी नहीं भूलता है। सेना के इस कदम से मां भारती के वीर बलिदानियों के परिवार भावुक हो उठे। सेना के अनुसार ये कार्यक्रम

विजय दिवस यानी 26 जुलाई तक आयोजित किये जायेंगे और इनमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले नायकों की अदम्य भावना, बलिदान और साहस का सम्मान किया जाएगा।

देश में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है जो राष्ट्र के दिल में गौरव और गंभीर यादों के साथ अंकित है। वर्ष 1999 में इसी दिन भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ कर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कारगिल की चोटियों को उनके कब्जे से छुड़ा कर ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा किया था।

पिछले 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया: मोदी

नई दिल्ली 10 जून (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में पिछले 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और सरकार ने रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के मौके पर शीर्ष नेतृत्व की ओर से सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख



किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में देशवासियों के सामूहिक संकल्प और रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता तथा प्रौद्योगिकी में

उत्कृष्टता की ओर ले जाने के अटूट दृढ़ संकल्प पर गर्व व्यक्त किया।

श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पिछले 11 वर्षों में हमारे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसमें आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। देशवासी भारत को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ जिस तरह से एकजुट हुए हैं यह देखकर खुशी होती है।

नई दिल्ली 10 जून (एजेंसियां)।

देश के अग्रणी इस्पात उत्पादक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय ने अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (ईईओ) - टियर-2 का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया गया है।

कंपनी ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि सेल को यह महत्वपूर्ण मान्यता 09 जून, 2025 को मिली। यह कंपनी की मजबूत आंतरिक नियंत्रण



प्रणालियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों के प्रति कड़ी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सेल के कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर) ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय, नई दिल्ली के प्रधान आयुक्त से यह महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के ईईओ कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना और एक

सुरक्षित व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा देना है।

यह उन कंपनियों को विशेष लाभ प्रदान करता है जो सीमा शुल्क कानूनों का पालन करने और अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती हैं। दुनिया भर में स्वीकार्य यह प्रमाण किसी भी संगठन के लिए अनुपालन, सत्यनिष्ठा और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा के प्रति उसकी निष्ठा का प्रमाण है।

मोदी सरकार के 11 साल पर बोले योगी आदित्यनाथ नया भारत शांति की रट नहीं लगाता, मुंहतोड़ जवाब देता है

लखनऊ, 10 जून (एजेंसियां)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष का कार्यकाल भारत वर्ष के स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा। इस कार्यकाल में पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक पहचान दी है। कांग्रेस समेत अन्य अस्थिर सरकारों से जो आम जन का विश्वास टूटा था। वैश्विक मंच पर जो भारत की छवि तार तार हुई थी उसे पीएम मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, तृष्टिकरण और परिवारवाद से मुक्त नेतृत्व ने भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाकर अगले 25 वर्ष की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। इन 11 वर्षों ने सामाजिक और संस्कृतिक पक्ष के साथ ही सेवा, सुशासन के साथ आर्थिक मोर्चे पर देश को एक नई पहचान दी है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्य प्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही शासन की नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं हैं। इन वर्षों ने विरासत और विकास का समन्वय करते हुए देश को दुनिया में नई पहचान दिलाई। अब चेहरा देख कर नहीं बल्कि जरूरत देख कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 11 साल में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और आतंकवाद के प्रति जारी टॉलरेंस को हमने देखा है। यह 11 साल का समय उस वक्त पूरा हो रहा है जब भारत की सामरिक शक्ति को



पूरे विश्व ने देखा है। पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में टूस्टेड भारत की सैन्य शक्ति मानी गई है। कोई हम पर युद्ध थोपेगा तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आपरेशन सिंदूर से दिया जाएगा। अब भारत दुनिया में शांति की रट लगाने वाला देश नहीं है बल्कि युद्ध थोपने पर कड़ा जवाब देने वाला देश है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन 11 वर्षों में भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। विकसित भारत के लिए पंच प्रण और 11 संकल्प बताए गए हैं। 11 साल में भारत ने विकसित भारत की आधारशिला पंच प्रण के आधार पर रखी है। समावेशी विकास शुरू किए गए हैं। ढांचागत विकास का मॉडल बनाया है। तकनीक के उपयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार पर काबू पाया गया। पिछले 11 साल में जितना कुछ तकनीक के माध्यम से किया गया पिछले 65 साल में नहीं हो सका था। वंशवाद और परावारवाद की राजनीति जातिवाद को भी बढ़ावा देती

है। ऐसी पुनरावृत्ति फिर ना हो जिसकी वजह से पहले देश को गुलाम होना पड़ा था।

मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हर हाल में आरक्षण की सुरक्षा की गई है। सामाजिक न्याय को सुरक्षित किया गया है। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने नए भारत का दर्शन किया। पिछले 11 वर्ष में भारत ने 11वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया। हमने उस ब्रिटेन को पछाड़ा जो हम पर 200 साल तक राज कर चुका है। भारत ने अपनी प्रति व्यक्ति आय को 11 साल में दोगुना किया है। भारत का निर्यात कई गुना बढ़ा है। भारत की विकास दर जिस तरह बढ़ रही है उससे 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।

मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की सांस्कृतिक और धार्मिक नगरों को पहचान दी गई। अयोध्या में 500 साल

के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ तो देश भर के प्रमुख तीर्थस्थानों का नया स्वरूप हमारे सामने आया है। अयोध्या को विश्वभर में धार्मिक नगरी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसके साथ ही सरकार पटेल की भव्य प्रतिमा की स्थापना और नेता जी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मान देना। मोदी सरकार ने देश की विरासत को विकास के साथ जोड़ा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को गति प्रदान करती प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन धन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी अनेक लोक-कल्याणकारी पहलें आमजन के जीवन को सुगम, वंचित को सशक्त और व्यवस्था को परिणाम दायक बनाने के प्रति प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। विरासत से विकास तक, मेट्रो की रफ्तार से सस्ती-सुगम हवाई यात्रा तक, वंदे भारत ट्रेनों से नए राजमार्गों तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कृषि से कॉमर्स तक, राष्ट्रीय सुरक्षा से सामाजिक सुरक्षा तक, सामाजिक समृद्धि से सामाजिक न्याय तक, भारत विविध क्षेत्रों में विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। आस्था, अस्मिता, आजीविका और अर्थव्यवस्था के उत्कर्ष को सुनिश्चित करते सेवा के 11 साल भारत को महाशक्ति बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

पुलिस भर्ती में चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते अमित शाह



लखनऊ, 10 जून (एजेंसियां)।

यूपी पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री से भेंट कर उन्हें कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में सभी चयनित अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपोजे ग्राउंड में होना प्रस्तावित है। इसके लिए सभी जिलों के कमानों से चयनित अर्थर्थियों को राजधानी भेजने को कहा गया है। वहीं, लखनऊ पुलिस कमिश्नरट उनके रहने और खाने-पीने का बंदोबस्त करेगा। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री, गृह विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

नवचयनित सिपाहियों में 12048 महिलाएं भी शामिल हैं। पहली बार किसी पुलिस बल में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों के चयनित अभ्यर्थी भी हिस्सा लेंगे। तत्पश्चात 22 जून से सभी जिलों में जनरल ट्रेनिंग कोर्स के लिए भेज दिए जाएंगे। वहीं जुलाई माह से नौ माह का आधारभूत प्रशिक्षण लेने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भेजे जाएंगे।

सीएम योगी के दौरे से पहले 500 किलो विस्फोटक का जखीरा मिला सर्वे की आड़ में बहराइच में बिछाया जा रहा था विस्फोटक



बंगाल के 70 लोग गिरफ्तार, मजार को ध्वस्त किया गया

बहराइच, 10 जून (एजेंसियां)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहराइच दौरे के पहले पुलिस ने करीब 500 किलो विस्फोटक पकड़ा है, जिसे जमीन के अंदर बिछाया गया था। इस मामले में 70 बंगाली मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया है। बाहर से आकर यूपी में अशांति फैलाने की कोशिशों में लगे कट्टर इस्लामिक तत्वों ने एक मजार को अड्डा बना लिया था, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि हरदी इलाके के सिकंदरपुर गांव के पास करीब 200 लोग तीन गाड़ियों में आए और खुद को एक तेल कंपनी का सर्वे करने वाला मुलाजिम बताया। उन लोगों ने 20 किलोमीटर के इलाके में जमीन में छेद करके अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बिछाना शुरू कर दिया। ये विस्फोटक बाल-तराय, लखनापुर, सधुवापुर, सिकंदरपुर और औराही जैसे कई गांवों में बिछाए गए थे। गांव वालों ने तुरंत महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह को इस मामले की जानकारी दी। विधायक तुरंत मौके

पर पहुंचे और अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन शुरुआत में कोई नहीं आया। जब इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों को दी गई तब जाकर स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई। तुरंत एसडीएम, एसपी और अन्य बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां गाड़ियों में भारी मात्रा में विस्फोटक लदा हुआ मिला। विधायक सुरेश्वर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि इतना विस्फोटक मिलने के बाद भी स्थानीय पुलिस अधिकारी गांव वालों पर गाड़ियों को छोड़ने का दबाव डाल रहे थे।

विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। बहराइच के ग्रामीण एसपी डीपी तिवारी ने बताया कि अब तक 70 लोगों को पकड़ा गया है और इनमें से ज्यादातर पश्चिम बंगाल के हैं। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने पहले ही पुलिस को अलर्ट किया था कि 37 बांग्लादेशी और रोहिंया घुसपैठिए नेपाल की सीमा से होते हुए बहराइच में घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन बहराइच पुलिस पर इन सूचनाओं का कोई असर नहीं पड़ा।

केजीएमयू के अध्ययन में निकला निष्कर्ष, रिपोर्ट प्रकाशित
कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, न लगवाएं बूस्टर डोज

लखनऊ, 10 जून (एजेंसियां)।

कोरोना को लेकर आ रहे केस से घबराने की जरूरत नहीं है। न ही इसके लिए बूस्टर डोज लेने की जरूरत है। एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप वैक्सीन की दो खुराक ले चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तीसरी खुराक लेने की जरूरत भी नहीं है। आपके शरीर में कोविड-19 वायरस के खिलाफ पर्याप्त एंटीबॉडी हैं। एल्सेवियर से प्रकाशित केजीएमयू के साझा अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला है।

अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच हुए इस अध्ययन में लखनऊ समेत आसपास के 10 जनजात के 7643 निवासियों को शामिल किया गया। इनमें से 643 में सेलुलर एंटीबॉडी और 7000 में ह्यूमरल एंटीबॉडी की जांच की गई। सेलुलर एंटीबॉडी वालों में पांच से 12 वर्ष के 139 बच्चे, 13 से 17 वर्ष के 75 किशोर थे। बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी थी। ह्यूमरल एंटीबॉडी वाले समूह में सभी शामिल थे। इनके खून के नमूने लेकर एंटीबॉडी जांची गई। इसमें देखा गया कि बच्चों में



एंटीबॉडी का स्तर कम था। पहली के बाद दूसरी डोज लेने के बाद एंटीबॉडी का स्तर बढ़ा था। दो डोज लेने वालों में एंटीबॉडी की मात्रा काफी ज्यादा थी। वहीं, दूसरी के बाद तीसरी खुराक लेने वालों में एंटीबॉडी की मात्रा में नाममात्र ही वृद्धि देखने को मिली। ऐसे में दो खुराक ले चुके लोगों को तीसरी खुराक लेने की जरूरत नहीं है।

केजीएमयू के संक्रामक रोग प्रभारी डॉ. डी हिमांशु ने बताया कि ह्यूमरल और सेलुलर प्रतिरक्षा (एंटीबॉडी) शरीर की दो मुख्य प्रतिरक्षा प्रणाली हैं। ये शरीर को रोगजनक और अन्य खतरों से बचाने के लिए एक साथ काम करती हैं। ह्यूमरल प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए बी कोशिकाओं पर निर्भर करती है। सेलुलर प्रतिरक्षा वायरस

और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए टी कोशिकाओं के माध्यम से एंटीबॉडी को सक्रिय करती हैं। वायरस को खत्म करने के लिए बी कोशिकाओं को उसके ऊपर चिपकना पड़ता है। वहीं, सी कोशिकाएं वायरस या बैक्टीरिया को लंबे समय तक उसके संपर्क में आते ही खत्म करती रहती हैं। अध्ययन में शामिल लोगों ने कोवीशील्ड और कोवॉक्सीन लगवाई थी। जांच करने पर दोनों में एंटीबॉडी का स्तर समान मिला। इससे साफ है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी।

अध्ययन में केजीएमयू की डॉ. गीता यादव, डॉ. डी हिमांशु, डॉ. हरदीप सिंह मल्होत्रा, डॉ. अमिता जैन, डॉ. श्रुति रेड्डी, डॉ. अनिल कुमार वर्मा, डॉ. शैलेंद्र यादव, डॉ. नीरज कुमार शामिल थे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के राज्य सर्विलांस अधिकारी विकाससुंद अग्रवाल, कनाडा की मैनिटोबा यूनिवर्सिटी से रवि प्रकाश, उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट से जॉन एंथोनी और परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय से अनुज त्रिपाठी शामिल थे।

प्राथमिक स्कूलों में हुए बड़े पैमाने पर तबादले, आदेश जारी

लखनऊ, 10 जून (एजेंसियां)।

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जिले के अंदर परस्पर तबादले की सूची सोमवार को जारी कर दी गई है। शिक्षकों को 10 से 15 जून के बीच कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

इस स्कीम के तहत 4636 जोड़ों यानी कुल 9272 शिक्षकों को तबादले का लाभ मिला है। इन शिक्षकों को 10 से 15 जून के बीच कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में लगभग दो महीने से परस्पर तबादले की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत हाल ही में एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की सूची जारी की गई थी। इसमें 7000 से ज्यादा शिक्षकों को तबादले का लाभ मिला था। वहीं सोमवार को जिले के अंदर परस्पर तबादले की सूची जारी की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के अंदर परस्पर तबादले के लिए आवेदन लेकर, बीएसए से ऑनलाइन सत्यापन व शिक्षकों की ओर से बनाए गए जोड़े के क्रम में इन शिक्षकों को



परस्पर तबादला दिया गया है। इसकी सूची एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। शिक्षक व बीएसए इसके अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके

लिए अभिलेखों का ठीक से सत्यापन भी करेंगे।

वहीं बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बीएसए को जारी आदेश में

कहा गया है कि इन परस्पर तबादला पाने वाले शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियों में ही 10 से 15 जून के बीच कार्यभार ग्रहण व कार्यमुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएसए इस प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करें, इसमें लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी भी समीक्षा की जा रही है कि एक से दूसरे जिले में हुए हुए परस्पर तबादले में अभी तक कितने शिक्षक कार्यमुक्त किए गए हैं। पिछली बार हुए जिले के

अंदर परस्पर तबादले में लगभग 20 हजार शिक्षकों को इसका लाभ मिला था। किंतु इस बार अपेक्षाकृत तबादले का लाभ पाने वाले शिक्षकों की संख्या कम है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि अपने घर व जिले के पास तबादला पाने वाले शिक्षकों को यह बड़ा तोहफा है। अब शिक्षक और बेहतर तरीके से मन लगाकर पठन-पाठन का काम करेंगे।

15 जिलों में तबादले का मौका, 60 में अब जगह नहीं

लखनऊ, 10 जून (एजेंसियां)।

बेसिक शिक्षा विभाग ने जिलों में खाली स्थानों का विवरण जारी कर दिया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को परिषदीय विद्यालयों में एक से दूसरे जिले में तबादले के लिए खाली जगह का विवरण जारी कर दिया। इसके अनुसार बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती समेत 15 जिलों में ही तबादलों का मौका मिलेगा। बाकी 60 जिलों में जगह खाली नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी पदों के विवरण के अनुसार 15 जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में अडिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल में 13266, हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल में

410, अडिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल (6 से 8 तक) में 16009 व हेड मास्टर अपर प्राइमरी में 3369 शिक्षकों को तबादला लेने का मौका है। इसके माध्यम से पिछड़े जिलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की कवायद की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार बलरामपुर, बांदा, बहराइच, बदायूं, हमीरपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मिर्जापुर, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर व सोनभद्र में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक तबादला ले सकेंगे। इन रिक्तियों की सूची सोमवार को निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शिक्षक-छात्र अनुपात सुधारने के क्रम में व बच्चों की सुविधा को देखते हुए यह रिक्तियां जारी की गई हैं। इन जिलों से कोई

शिक्षक दूसरे जिले में तबादला नहीं लेंगे। वहीं अन्य 60 जिलों में अभी तबादले के लिए रिक्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि इन जिलों में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए हैं जो 12 जून तक चलेंगे। शिक्षक ऑनलाइन आवेदन की प्रतीक्षा करेंगे। बीएसए 14 जून तक ऑनलाइन सत्यापन कर डाटा लॉक करेंगे। वहीं एनआईसी 16 जून को तबादला सूची जारी करेगी। जबकि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्भय सिंह ने कहा कि एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को इस बार कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, एनसीआर आदि जिलों में जाने के लिए आवेदन नहीं किए जा सकेंगे।

मथुरा निगम की बैठक : बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव पास

मथुरा, 10 जून (एजेंसियां)।

मथुरा नगर निगम की बैठक में श्रीबांकेबिहारी की जयघोष के साथ प्रस्तावित श्रीबांकेबिहारी कॉरिडोर निर्माण का मौखिक रूप से प्रस्ताव पास हो गया है। अधिकतर पार्षदों ने सरकार की इस योजना का समर्थन किया, जबकि श्रीबांकेबिहारी मंदिर क्षेत्र के पार्षद घनश्याम चौधरी ने पुरजोर इसका विरोध किया। फिर घनश्याम चौधरी और अन्य पार्षदों में नोकझोंक शुरू हो गई और हंगामा होने लगा। बैठक का माहौल बिगड़ता देख महापौर ने पार्षदों को शांत कराया। पार्षद बोले मथुरा-वृंदावन का बच्चा-बच्चा कॉरिडोर निर्माण चाहता है। यह बैठक मसानी तिराहे के निकट

एक निजी होटल में आयोजित की गई। इस दौरान में महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त जग प्रवेश समेत सभी वाडों के पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा है कि श्रीबांकेबिहारी जी के दर्शन के लिए हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्रीबांकेबिहारी कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि मथुरा-वृंदावन के लोगों को महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन आराध्य के सुगमता से दर्शन नसीब नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण श्रीबांकेबिहारी मंदिर में भीड़ का दबाव है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर



स्थानीय लोग मंदिर जाने में संकोच करते हैं। यहीं नहीं उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए, जो मंदिर की अव्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ी है। इससे मथुरा के लोगों को अधिक कष्ट होता है। साथ ही कहा है कि भीड़ के दबाव के कारण व्यापार को भी चपत

लाग रही है। भीड़ के दबाव के कारण श्रद्धालु दुकानों पर रुकने की वजह बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। बिना कुछ खरीदारी किए श्रद्धालु चले जाते हैं। इसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए श्रीबांकेबिहारी कॉरिडोर का निर्माण समय की

आवश्यकता है।

महापौर की इस बात पर सभी पार्षदों ने एक स्वर में बांकेबिहारी के जयकारे लगाए। साथ ही कहा कॉरिडोर निर्माण समय की आवश्यकता है। हालांकि श्रीबांकेबिहारी क्षेत्र के पार्षद घनश्याम चौधरी ने इसका विरोध जताया है। उनका कहना है कि कॉरिडोर निर्माण से वृंदावन की कुंज गलियां समेत पुरातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी। साथ ही सैकड़ों लोग प्रभावित होंगे।

घनश्याम चौधरी के विरोध के बाद मौजूद अन्य पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया और घनश्याम को चारों तरफ से घेर लिया। माहौल बिगड़ता देख महापौर ने पार्षदों का शांत कराया। इस दौरान पार्षद

दल के नेता बालकिशन चुतुर्वेदी, नीनू कुंजबिहारी भारद्वाज, नीरज वशिष्ठ, ब्रजेश खरे, राजवीर सिंह, तेजवीर सिंह, संतोष पाठक, राकेश भाटिया और राकेश यादव समेत अन्य पार्षद मौजूद रहे।

महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा है कि गोस्वामी समाज की मांगों के अनुरूप ही कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इससे प्रभावित होने वाले किसी का भी अहित नहीं होगा। प्रशासन इसकी प्रक्रिया में लगा है।

साथ ही कहा कि गोस्वामी बिहारपुра में आवास चाहते हैं तो इसका भी हल निकाला जाएगा। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि गोस्वामी समाज के लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें।

पार्षद इसमें सहयोग करेंगे। महापौर ने कहा है कि कॉरिडोर निर्माण के अलावा श्रीबांकेबिहारी क्षेत्र में और विकास की आवश्यकता है।

इसमें उन्होंने सभी पार्षदों का सहयोग मांगा है। कहा है कि पिछले सात सालों में नगर निगम क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हुआ है। भले ही मथुरा-वृंदावन नगर निगम इंदौरा और बड़ौदा नहीं बन पाया हो, लेकिन विकास काफी हुआ है। आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। वहीं उन्होंने प्रस्तावित निर्माण नाले का निर्माण कराने का जूम्र किया। कहा है कि 90 करोड़ रुपये से भूमिगत नाले का निर्माण कराया जाएगा। इससे जलभराव की समस्या से निदान मिलेगा।

संपादकीय

गरीबी में कमी

विश्व

विश्व

बैंक की हालिया रिपोर्ट भारत में अत्यधिक गरीबी में आई उल्लेखनीय कमी को दर्शाती है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में यह दर 5.3 प्रतिशत रह गई है। जो वर्ष 2011-12 में 27.1 फीसदी थी। रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार भारत ने लाभार्ण एक दशक से कुछ कम समय में 27 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है, जो पैमाने और गति के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि कही जा सकती है। निश्चित रूप से इस उपलब्धि में विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों मूलतः आर्थिक विकास और ग्रामीण रोजगार योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है। निस्संदेह, इन्में सबसे प्रगति तबके के लोगों की आय बढ़ाने में मदद की है। निश्चित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण, बिजली, शौचालयों और आवास तक इस तबके की पहुंच बढ़ाने

पछले साल जारी की गई विश्व अस्मानता रिपोर्ट 2022 से पता चलता है कि भारत में शीर्ष एक प्रतिशत लोगों की संपत्ति में बड़ा उछाल आया है। वे लोग देश की चालीस फीसदी संपत्ति नियंत्रित कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों से देश में आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला है। वहीं तकनीकी प्रेरित सेवाओं में उछाल के चलते, वर्ष 2000 के बाद विकास मॉडल ने एक छोटे वर्ग को असंगत रूप से लाभान्वित किया है। निश्चित रूप से नई आर्थिक नीतियों की विसंगतियों से उपजे असमान परिदृश्य में लाखों लोग गरीबी की रेखा से ऊपर तो उठ गए, लेकिन वे बीमारी, नौकरी छूटने या जलवायु परिवर्तन से उपजी आपदाओं जैसे संकटों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक रूप से हाशिये पर रहने वाली आबादी के बड़े हिस्से के लिये यह खतरा बना हुआ है। एक मजबूत सुरक्षा कवच का अभाव इस संकट की संवेदनशीलता को बढ़ा देता है। भारत के विकास की गाथा तभी लिखी जा सकती है, जब हम इस असमानता की खाई को पाटकर कम कीमत के कपड़े की दिशा में आगे बढ़ें। निर्विवाद रूप से सामाजिक न्याय के लिये गरीबी कम करने के साथ, समानता के लिये भी

सम्मान, समानता और नीतियों में लचीलापन जरूरी है। वास्तव में गरीबी मुक्त भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब सरकार की कल्याणकारी नीतियों ने केवल उन्हें गरीबी के दायनत्व से बाहर निकाले, बल्कि उन्हें स्वावलंबी भी बनाए। आर्थिक कल्याणकारी नीतियों का मकसद मुक्त और स्वयंसेवा बंटना न होकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए। निर्धन आबादी के लिये जनकल्याण की योजनाएं जरूर चलाई जानी चाहिए, लेकिन एक वक्त के बाद सरकारी सहायता पर उनको निर्भरता को कम करना भी उतना ही जरूरी है। वहीं दूसरी ओर, शिक्षा के प्रसार से इस वर्ग की उत्पादकता बढ़ाने की भी कोशिश की जानी चाहिए। तभी गरीबी का कुचक्र स्थायी रूप से कम किया जा सकता है।

आप का नजरिया

भारत के स्वराज्य की हुंकार

हिन्दू साम्राज्य दिवस

छत्रपति

मुसलमानों के लंबे शासन और अत्याचारों के कारण भारत का मूल समाज आत्मेन्द्रियों की स्थिति में चला गया था। विशाल भारत के किसी न किसी भू-भाग पर मुसलमानों के शोषणकारी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष तो चल रहा था लेकिन उन संघर्षों से बहुत कम उम्मीद नहीं थी। भारत के वीर समुत्त अपने प्राणों की बाजी तो लगा रहे थे लेकिन समाज को जो गुनाह और संघटित करने का काम नहीं कर पा रहे थे। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के भीतर विरवाज जगाए कि हम मुगलों के शासन को खंड से उखाड़कर फेंक सकते हैं, यदि सब एकजुट हो जाए। यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के देवलोकावमान के बाद भी 'हिन्दीवी स्वराज्य' का विचार प्रचलित, पुष्टि और विस्तारित होता रहा। 'हिन्दु' साम्राज्य दिवस' या 'श्रीषिव' राज्याभिषेक दिवस' भारतीय इतिहास को महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने दुनिया को बताया कि भारत के भाग्य विधाता मुगल नहीं थे। भारत का हिन्दु समाज ही भारतीय का भाग्य विधाता है। भारत में हिन्दुओं का राज्य है। उनके शासन का नाम है- 'हिन्दीवी स्वराज्य'। [विजय संवत् 1731, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को स्वराज्य के प्रणेतो एवं महान शासक राजा श्रीषिव छत्रपति के राज्याभिषेक पर 1600 पद पादशाही की स्थानाभ्यास से भारतीय इतिहास को नयी दिशा मिली। दासता के घोर अंधकार में स्वराज्य की एकल चमकदार रोशनी था- हिन्दीवी स्वराज्य। हिन्दु साम्राज्य दिवस को हम भारत के स्वराज्य की हुंकार भी कह सकते हैं, जब हिन्दुओं ने आत्मविश्वास से सीना ठोककर मुगलों को ललकारा और कहा कि भारत में एक बार फिर स्वराज्य की स्थानाभ्यास हो गई है, जिसमें सबका हिस्सा है। अनेक इतिहासकार एवं विद्वान कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिन्दीवी स्वराज्य की स्थापना न की होती, तो भारत का इतिहास कुछ और होता। यह अतिशयोक्तिपूर्ण विचार नहीं है। अपितु भारत के पड़ोसी देशों एवं दूर-दूरान्त के उन देशों की स्थिति को देखकर सहज कल्पना की जा सकती है, जहाँ मूल समाज की अपेक्षा बाहरी आक्रांताओं का शासन स्थायी हो गया। ऐसे देशों में वहाँ के मूल समाज की संस्कृति लगभग समाप्त हो गई है। हम कल्पना ही कर सकते हैं कि जिस प्रकार के अत्याचार मुगल शासन भारत में कर रहे थे, उसके बाद ही हिन्दु समाज किस स्थिति को प्राप्त होता। प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार जीएस सरदेसाई ने लिखा है कि "मुस्लिम शासन के अधीन पूर्ण अंधकार छाया हुआ था। न कोई प्रभुता होती थी, न यन्त्रिय मिलता था। अधिकारी जो चाहें, वही करते थे। स्त्रियों के सम्मान का हानन, हत्याएं, हिंसा का जबरन भय परिवर्तन, उनके मंदिरों का विध्वंस, साम्राज्य का वध- ऐसे ध्वनिने अत्याचार उन शासन में आम बात थे। निजामशाही ने तो खुलेआम जोजाबाई के पिता, उनके भाइयों और पुत्रों की हत्या कर दी थी। फलटन के बजाय जी निलालकर को जबरन मुसलमान बनाया गया। ऐसे अनिष्टों का उदाहरण दिया जा सकते हैं। हिंदू धम्मजानमान की जीवन नहीं जी सकते थे। यही बात थी, जिन्होंने शिवाजी के भीतर धम्मजानमान क्रोध जगा दिया। विद्रोह की प्रबल भावना ने उनके मन को पूरी तरह घेर लिया। उन्होंने तुरंत काम आरंभ कर दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिसके हाथ में शस्त्र की शक्ति है, उसे कोई भय नहीं होता, कोई कठिनाई नहीं आती"। औरंगजेब का शासन तो हिन्दुओं के लिए किसी नरक से कम नहीं था। मुगलों के अनीतिपूर्ण शासन के बरक्स छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य ने लोकहित सर्वोपरि था। उन्होंने शासन को 'स्व' के आधार पर विकसित किया, इसलिए वह सबका अपना स्वराज्य था।

टैरिफ को लागू करने की तारीखों में परिवर्तन किया जा रहा है तो कभी टैरिफ को कम किया जा रहा

भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक के दो महत्वपूर्ण तोहफे

प्रह्लाद सबनानी



भारत में नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रति कटिबद्ध हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के उपक्रम एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियां देश के आर्थिक विकास को गति देने में अपने प्रयास लगातार तेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 6 जून 2025 को द्विमासिक मुद्रा नीति की घोषणा करते हुए, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से, दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक, रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे 6 प्रतिशत की दर से नीचे लाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

वैश्विक

वैश्विक

स्तर पर विश्व के कई देशों में आर्थिक गतिविधियों पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में तो श्री डॉनल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद से अनिष्ट नई घोषणाएं की जा रही है। कभी टैरिफ को बढ़ाया जा रहा है तो कभी टैरिफ को लागू करने की तारीखों में परिवर्तन किया जा रहा है तो कभी टैरिफ को कम किया जाता रहा है। कुल मिलाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अफरा पफरी का मौला लग बग्या है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री ट्रम्प एवं अमेरिका के एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली मंत्री श्री एलान मस्क के बीच युद्ध छिड़ गया है एवं अब एक दूसरे पर गम्भीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का इन सब बातों से बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी भत्ता लेने वाले नागरिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अमेरिकी कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी पर विचार किया जा रहा है एवं आर्थिक विकास दर काम हो रही है। दूसरी ओर, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने के आसार अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तरह से इजरायल, हम्मस के बीच युद्ध अभी भी जारी है। चीन एवं अमेरिका के बीच में अब खांटसा भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वैश्विक स्तर पर इन समस्त घटनाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था निचट नहीं ऊँचाईयों को छुने की ओर अग्रसर है। भारत में नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रति कटिबद्ध है। कैसे एवं राज्य सरकारों के उपक्रम एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों देश के आर्थिक विकास को गति देने में अपना प्रयास लगातार तेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 6 जून 2025 को डिमांड्स मुद्रा नीति की घोषणा करते हुए, देश को अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से, दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक, रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे 6 प्रतिशत की दर से नीचे लाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है। फेडरल रखा 2025 में रेपो दर में यह लगातार तीसरी कटीौ की गई है एवं कुल मिलाकर रेपो दर में 100 आधार बिंदुओं की कमी की जा चुकी है। फरवरी 2025 एवं अप्रैल 2025 घोषित की गई मुद्रा नीति के माध्यम से रेपो दर में दोनों बार 25 आधार बिंदुओं की कमी की गई थी। रेपो दर उस दर को कहते हैं, जिन दर पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं विभिन्न बैंकों का आवश्यकता पर धन ऋण उपलब्ध करता है एवं विभिन्न बैंक रेपो दर को आधार दर बनाते हुए इस दर पर कुछ आधार बिंदु (नेमाराशि की लागतता एवं लाभ की राशि का समायोजन करते हुए) जोड़ते हुए, व्याज की दर पर, अपने ग्राहकों को ऋणारशि उपलब्ध कराते हैं। दूसरे, भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात में



सीधे ही 100 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे 4 प्रतिशत की दर से घटाकर 3 प्रतिशत की दर पर ला दिया है। इससे, भारत में बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध हो जाएगी एवं सिस्टम में तरलता बढ़ जाएगी। नकद आरक्षित अनुपात उस अनुपात को कहते हैं, जिस पर विभिन्न बैंकों को अपने मांग एवं जमा देयताओं की राशि पर इस अनुपात की दर से नकद राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करनी होती है। अतः यह राशि इन बैंकों की पहुंच से बाहर हो जाती है एवं ऋण के रूप में इसे बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। यदि नकद आरक्षित अनुपात को कम कर दिया जाता है तो बैंकों के पास यह राशि ऋण के रूप में प्रदान करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। इससे स्पष्टतः बैंकों की लाभप्रदता में सुधार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त महत्वपूर्ण दोनों निर्णयों से वैश्विक स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत में उत्पादों की आंतरिक मांग उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी क्योंकि बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋणराशि पर ब्याज दरों को कम करेंगे। इससे, विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण, आदि सस्ते होंगे और अब प्रति माह ग्राहकों द्वारा इन ऋणों पर अदा की जाने वाली मासिक किश्त की राशि में कमी आएगी और इन नागरिकों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने लगेगी। जिसे वे अन्य पदार्थों को खरीदने में खर्च कर सकेंगे। साथ ही, ऋण पर ब्याज राशि कम होने से विभिन्न उत्पादक कम्पनियों की लाभप्रदता में वृद्धि होगी क्योंकि उन्हें अब बैंकों से लिए गए ऋण पर कम ब्याज देना होगा। लाभप्रदता में होने वाली इस अतिरिक्त वृद्धि के चलते यह कम्पनियाँ अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के बारे में गम्भीरता से विचार करेंगी क्योंकि उत्पादों की होने वाली मांग में वृद्धि की पूर्ति जो करनी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2025 माह में घोषित मौद्रिक नीति को अर्थशास्त्रियों एवं बैंकिंग जगत के विशेषज्ञों द्वारा हाल ही के वर्षों में घोषित की गई सबसे बेहतर नीति मौद्रिक नीति माना जा रहा है। इस मौद्रिक नीति को भारत के शेयर

जकार ने भी दिनांक 6 जून 2025 को त्वरित सकारात्मक उत्तर दिया और निफ्टी एवं सेन्सेक्स में एक प्रकृतिशत से अधिक की, रोलवर्स हुई हैं। ब्याज दरों से जुड़े शेयरों विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय एस्टेट एवं औद्योगिक क्षेत्रों की कम्पनियों के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। दरअसल अधिकतर अर्थशास्त्री रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की उम्मीद कर रहे थे परंतु भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 आधार बिंदुओं की कमी की घोषणा करते हुए अपनी आक्रामक नीति का पतित्व दिया है। अतः रेपो दर में उम्मीद से अधिक कटौती होने पर निवेशकों का भारतीय कम्पनियों, विशेष रूप से वे कम्पनियाँ जो परेल्ड कम्पनियों पर निर्भर रहती हैं, पर भरोसा बढ़ा है। भारतीय कम्पनियों की लाभप्रदता एवं उत्पादों की विविधता में लगातार हो रहे तेज सुधार के चलते इन भारतीय कम्पनियों की साख अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ी है। आगे आने वाले समय में यह कम्पनियाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का स्वरूप भी ले सकत हैं। और फिर, ब्याज दरों में लगातार की जा रही कमी के चलते इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की उत्पादन लागत भी कम होगी जिससे इन कम्पनियों के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्ध में बन सकेंगे। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने स्टेन्स को अकमोडेटीव से न्यूट्रल जरूर कर दिया है जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर में आगे आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर बढ़ौतारी कर सकता है। जबकि अकमोडेटीव स्टेन्स में रेपो दर में केवल कमी करने की सम्भावना निहित रहती है। परंतु, आगे आने वाले समय में यदि मंहगाई की दर पर नियंत्रण बना रहता है जिसकी सम्भावना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी की गई है और औसत मंहगाई दर के अनुमान को 4 प्रतिशत से घटाकर 3.70 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः बहुत सम्भव है कि भारतीय रिजर्व बैंक को न्यूट्रल स्टेन्स के बावजूद रेपो दर में कमी ही करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंहगाई की दर में आई कमी एवं विकास दर में आई सुधार को देखते हुए रेपो दर एवं नकद आरक्षित अनुपात में आक्रामक रूप से की गई कटौती को एक सकारित निर्णय कहा जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में खपत एवं निवेश जगमग अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अपने पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने पर विचार करेगा। चूँकि भारत में मुद्रा स्फीति की दर अब नियंत्रण में है अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में विकास दर को बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। हालाँकि अपने स्टेन्स को न्यूट्रल रखकर मुद्रा स्फीति एवं वैश्विक स्तर पर विभिन्न जोखिमों पर भी नजर बनाए रखने का आभास दिया है।

देश

दुनिया से

राष्ट्रवाद की आड़ में ट्रंप का परिवारवाद

देश

देश में दलगत नेताओं के परिजनों, संबंधीजनों तथा स्वजनों को राजनैतिक दबाव के चतुर्ते लाभ देने के अनेक उदाहरण आज भी पैदा हो रहे हैं। अचानक पूंजीपति बनने वाले की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी औपचारिकताओं को हाशिये पर रखकर सुविधाएँ पहुँचाने के अनेक मामल स्वस्थानीय के बाद से ही सामने आते रहे हैं। यूँ तो घोटालों की लम्बी पेरिस्ट है परन्तु बानगी के तौर पर सन1948 का जीप खरीद घोटाला जिसमें वीके मेनन, सन1951 का साइकिल आयात घोटाला जिसमें एस्प वेंकटरमण, सन1956 का बीजचू फण्ड घोटाला, सन1958 का हरिदास मूंदडा मामला जिसमें टीटी वृष्णाभायारी, सन1960 का तेजा लोन स्वेम, सन1963 का प्रताप सिंह वैरो स्वेम, सन1965 का पटनायक 'कलिंग टूल्स' मामला जिसमें बीजू पटनायक, सन1975 का मारुति घोटाला जिसमें इंदिरा गांधी, सन1976 का नुमा आयरल डील, सन1981 का अंतुले ट्रस्ट मामला जिसमें एआर अंतुले, सन1987 का एचडीडब्ल्यू दलाली मामला, सन1987 का बोफोर्स घोटाला जिसमें राजीव गांधी, सन1989 का सेंट कित्स मामला जिसमें वीपी सिंह, सन1990 का चारा घोटाला जिसमें लालू प्रसाद यादव, सन1991 का हवाला घोटाला जिसमें एसके जैन, सन1992 का हर्षद मेहता काण्ड, सन1992 का इंडियन बैंक मामला, सन1992 का भास्वे स्टॉक एक्सचेंज घोटाला जिसमें हर्षद मेहता, सन1992 का सिस्क्यूरीटी स्वेम, आईपीएल घोटाला जिसमें ललित मोदी, सत्यम घोटाला, स्ट्याम्प घोटाला, सन1993 का झारखण्ड मुक्ति मोर्चा मामला जिसमें शिबू सोरेन, सन1994 का चीनी घोटाला जिसमें कल्पनाथ राय, सन1995 का जूता घोटाला जिसमें सोहिद दया, तहलका काण्ड जिसमें जार्ज फर्नान्डो, लक्खू भार्द

पाठक मामला जिसमें नरसिंहराव, सन 1999 का हसन अनली टैक्स मामला, कामानवेल्थ गेम्स घोटाला जिसमें मनीमोहन सिंह, विजय माल्या प्रकरण, पीएनबी घोटाला जिसमें नीरव मोदी तथा मेहुल चौकसी, रोटोमैक घोटाला, सन 2000 का मैच फाक्सग घोटाला, बराक मिसाइल सौदा मामला, यूटीआई घोटाला, तेल के बदले अनाज मामला जिसमें नटवर सिंह, ताल वैरीडोर मामला जिसमें मायावती, कोडा मनीलांडरिंग मामला जिसमें मधु कोडा, ताबूत घोटाला, सन 2002 का टेलीकाम स्वैम जिसमें सुखराम शर्मा, यूरिया घोटाला जिसमें सीएस रामचृणन, सन 2007 का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला जिसमें ए. राजा, सन 2010 का आदर्श हाउसिंग आईपी जिसमें अशोक चव्हाण, सन 2012 का वीवीआईपी हेलिकाप्टर घोटाला जिसमें एसपी त्यागी, सन 2012 का नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें सोनिया गांधी सन 2013 का डीएलएफ भूमि हडप मामला जिसमें राबर्ट बाड्रा, सन 2013 का केरल सौर पैन्ल घोटाला जिसमें सीएम चांडी, सन 2015 का वोट के लिए नोट मामला जिसमें एल्लिस स्टीपेसन, सन 2020 का केरल गोड तस्करी मामला जिसमें पिनाराई विजयन, सन 2022 का शराब घोटाला जिसमें अरविन्द केजरीवाल पर भी गम्भीर आरोप लगाये गये थे। सत्ताधिकार के सामने मुद्दे खोलने वालों का हमेशा ही दुर्गति होती रही है। निजी स्वार्थों की परकृति के लिए पद के दुरुपयोग का पैशन सा चल निकला है। अब तो पद के योगाओं को आदर्श मानकर विदेशों में भी यह शीतियां तेजी से विकसित हो रही हैं। आपरेशन सिद्ध के दौरान अमेरिका का पाकिस्तान के साथ सहयोगात्क रवैया यूं ही नहीं रहा है। ज्ञातव्य है कि कश्मीर के पहलगाम में विगत 22 अप्रेल को इस्लामिक आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। भारतीय नागरिकों का आक्शोश

और सरकार का कड़ा रुख देखते हुए पाकिस्तान ने 27 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और पुत्र एरिक ट्रंप, डोनाल्ड जूनियर की वीरायो को समर्पित कम्पनी वल्ल लिबर्टा फाइनैशियल से एक अनुबंध कर लिया। यह अनुबंध सन2024 में गठित अमेरिकी कम्पनी वल्ल लिबर्टा फाइनैशियल तथा सन2025 में गठित पाकिस्तान गिरो को कार्सिल के मध्य हुआ जिसमें कार्सिल की ओर से चांग पैंग झाओ को सलाहकार नियुक्त किया गया। इस पूरे परिदृश्य में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने पुत्र सलमान शहबाज की कम्पनी एसएसई टेनोबलजीज को वीरायो माइनिंग नेटवर्क तैयार करने हेतु जोड़ दिया। उल्लेखनीय है कि पहलगाम हमले के ठीक पहले पाकिस्तान वीरायो को कार्सिल की स्थापना की गई थी। यानी यह सब वृष्ट पुर्न विधातित षडयंत्र के तहत चल रहा था जिसमें राष्ट्रवाद की आड में ट्रंप का परिवारवाद पूरी तरह से शामिल था। वास्तविकता तो यह है कि अमेरिकी आवाम के अजांकृत होने के कारण वीरायो को वहां पर औपचित्य विस्तार पाने में कठिनाई हो रही है जिसका विकल्प पाकिस्तान को बनाया जा रहा है ताकि यहां से ट्रंप परिवार की कम्पनी दुनिया भर में पांव पसार सके। ऐसा ही परिवारवाद तरकिये के राष्ट्रपति रजब तैयिब अदरआन के वृत्यों भी से स्पष्ट होता है। उनकी पुत्री सुमैयै अदरआन का निकाह सेल्युक वायरात से हुआ था जोकि बायकार कम्पनी का मुखिया है। यह कम्पनी बायकार वीहा छ्ठ सहित अनेक खतरनाक डौन बनानी है जिसका युद्ध के मैदान में उपयोग होता है। तरकियै के राष्ट्रपति अदरआन के दामाद ने पाकिस्तान को न केवल युद्ध में उपयोग होने वाले खतरनाक डोन्स की आपरुति की बल्कि डोन्स अपरसेड्स भी उपलब्ध कराये ताकि भारत को पराजित किया जा सके।

दृष्टि

कोण

भारत की स्त्री-केंद्रित सभ्यता की झलक

हरियाणा

हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है, जहाँ से मिले 4600 साल पुराने महिला कंकाल, शंख की चूड़ियाँ और ताम्र नृत्यांगना की प्रतिमा सभ्यता में स्त्री की केंद्री भूमिका को रेखांकित करते हैं। डीएनए विश्लेषण ने 'आर्य आक्रमण सिद्धांत' पर सवाल उठाया है और भारत की सांस्कृतिक निरंतरता को सिद्ध किया है। राखीगढ़ी अब केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं, बल्कि संस्कृति के अतीत की आत्मा से सटीकता को जीवंत माध्यम है। हरियाणा के हिसार जिले का एक सामान्य-सा गांव राखीगढ़ी, अब वैश्व पुरातात्विक विमर्शों का केंद्र बन चुका है। 1997-99 के दौरान हुए उत्खननों ने इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में गिना जा शुरु किया, और 2012 में विश्व विरासत को जोष की 'खरने में पड़ी धरोरे' की सूची में इसकी उपस्थिति ने वैश्विक ध्यान खींचा। परन्तु इसके



के आगमन को जोड़ा जाता है। यह निष्कर्ष 'आर्य आक्रमण सिद्धांत' को एक बड़ा झुकाव देता है। यह एक संकेत देता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक विकास अपनी निरंतरता में हुआ।

मोहेंजोदड़ो की विश्वप्रसिद्ध कांस्य नर्तकी को तरह, राखीगढ़ी से भी एक ताम्र प्रतिमा मिली है जिससे 'डांसिंग गर्ल' कहा जा रहा है। यह मूर्ति न केवल सौंदर्यबोध और कलात्मकता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि उस काल में नारी की उत्थिति सांस्कृतिक और सार्वजनिक जीवन

मे किन्ती सशक्त रही होगी। यह मान्यता को चुनौती देती है कि प्राचीन सभ्यताओं में स्थिरता केवल घरेलू क्षेत्र में सीमित थी। अंकाल मिलने के कारण प्र. अफिरावियों को के अग्रश्रेणी मिले हैं। जो यह संकेत करते हैं कि शवदाह की परंपरा उस समय भी प्रचलित थी। अर्जुन, जिसे वैदिक परंपरा में शुद्धिकरण और संस्कार का प्रतीक माना गया है, उसका हड़प्पा मान में वैदता महत्वपूर्ण स्थान होना यह इंगित करता है कि वैदता और हड़प्पा परंपराएं एक-दूसरे से पूर्णतः असंबंधित नहीं थीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि महाभारत युद्ध लगभग 5000-5500 वर्ष पूर्व हुआ था। यदि यह मान लिया जाए, तो राखोड़ी की स्थापना इस युद्ध से पहले की जानी जा सकती है। एक किंवदंती यह है भी है कि महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाएं यहीं शरण लेने आई थीं और वहीं से इस स्थान का नाम 'राखोड़ी' पड़ा — 'राख' यानी मृत्यु की राख, और 'गढ़ी' यानी

शरण। ऐसी मिथकीय व्याख्याएँ ऐतिहासिक सत्य नहीं हैं, परंतु ये वह दर्शाती हैं कि स्थानीय जनमानस में राखीगढ़ी की सांस्कृतिक स्मृति कितनी गहरी है। राखीगढ़ी से मिले महिला कंकाल का जीवोन्मिक विश्लेषण केवल पुरातत्व नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास-लेखन में एक बड़ा मोड़ है। स्टेपी डीएनए की अनुपस्थिति सीधे उस विचारधारा को चुनौती देती है जिसने लंबे समय तक 'आर्य आक्रमण' को भारत में सभ्यता के आगमन का कारण बताया। इस अध्ययन ने इतिहास, नृविज्ञान और भाषाविज्ञान के विशेषज्ञों को एक बार फिर सोचने पर विवश किया है कि क्या आर्य वाहुर से आये थे या नहीं के थे। क्या वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति में कोई 'टकराव' नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रवाह था? राखीगढ़ी की खोजों के परिणाम अब एनसीआईआरटी जैसे शैक्षिक निकायों के पाठ्यक्रम में भी दिखाई दे रहे हैं।



जासूसी उपन्यास द डे ऑफ द जैकाल के लेखक फ्रेडरिक फोर्सिथ का 86 वर्ष की आयु में निधन

लंदन, 10 जून (एजेंसियां) ।

रहस्य और रोमांच की दुनिया में सत्तर औसरी के दशक के बीच में सबसे ज्यादा पढ़े गए जासूसी उपन्यास द डे ऑफ द जैकाल के लेखक फ्रेडरिक फोर्सिथ का सोमवार को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ब्रिटिश लेखक फोर्सिथ बेहतरीन सेन्य पायलट भी थे। उन्होंने अपना कर्ज चुकाने के लिए लेखन को चुना। फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लगभग 25 से अधिक उपन्यास लिखे। दुनिया भर में इन उपन्यासों की 70 मिलियन प्रतियां बिकीं।

रिपोर्ट के अनुसार, उनके प्रवक्ता जोनाथन लॉयड ने उनके निधन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जासूसी उपन्यास द डे ऑफ द जैकाल के अलावा फोर्सिथ के द ओडेसा फाइल और द डॉग्स ऑफ वॉर को भी पाठकों का भरपूर प्यार मिला। उनके प्रकाशक बिल स्कॉट-केर ने कहा, उन्हें दुनिया भर में पढ़ा गया। उनके समकालीन

लेखक भी उनकी लेखन शैली का लोहा मानते थे। वह अपने पीछे अद्वितीय विरासत छोड़ गए हैं। वह अपने उपन्यासों में हमेशा जिंदा रहेंगे।

1938 में केंट में जन्मे फोर्सिथ 18 साल की उम्र में आरएएफ में शामिल हुए। इसके बाद बीबीसी और रॉयटर्स के लिए युद्ध संवाददाता बन गए। उन्होंने 2015 में खुलासा किया कि उन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआई-6 के लिए भी काम किया। उनके उपन्यासों के कई काल्पनिक कथानक दुनिया भर में उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित थे। उन्होंने 1971 में बेरोजगारी के समय अपना पहला उपन्यास द डे ऑफ द जैकाल लिखा। इसकी सफलता पर उन्होंने कहा था- मैं कैंगाल था। कर्ज में डूबा था। मेरे पास फ्लैट नहीं था। कार नहीं थी। कुछ भी नहीं था। और मैंने सोचा- मैं खुद को इस गड्डे से कैसे निकालूँ मुझे शायद सबसे अजीब समाधान मिला- एक उपन्यास

लिखो। दो साल बाद 1973 में द डे ऑफ द जैकाल पर फिल्म बनाई गई। इसमें जैकल की भूमिका एडवर्ड फोक्स ने निभाई। पिछले साल एडी रेडमेन ने इस उपन्यास पर टीवी धारावाहिक बनाया। उनके प्रवक्ता लॉयड ने बयान में कहा कि वह कुछ समय से बीमार थे। उन्होंने सोमवार को हमेशा-हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लॉयड ने कहा, हम दुनिया के सबसे महान थ्रिलर लेखकों में से एक के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। वह सफल युद्ध संवाददाता रहे। उनका जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषा पर समान अधिकार था। वह बियाफ्रा में विदेशी संवाददाता बन गए। वह एक सीक्रेट सर्विस एजेंट भी रहे। उनके प्रकाशक स्कॉट-केर ने कहा कि फोर्सिथ के साथ काम करना मेरे पेशेवर जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि शानदार कथानक और विचारों के प्रवाह को छोड़कर, वह सबसे पेशेवर लेखक थे, जिसकी एक संपादक उम्मीद कर

सकता है। फोर्सिथ की मित्र गायिका एलेन पैज ने एक्स पर लिखा, मुझे फोर्सिथ के निधन पर दुख है। स्थानों, महलों और भूगोल के बारे में उनका अकादमिक ज्ञान बेजोड़ था। उन्हें कई कारणों से बहुत याद किया जाएगा। अंग्रेजी संगीतकार एंड्रयू लॉयड वेबर ने कहा, उन्होंने वास्तव में रोमांस और रोमांच के लिए अपनी आंखें फ्रेडरिक, ऐसी कहानियां बनाने के लिए जो आपके सम्मान में पीढ़ियों तक जीवित रहेंगी। कंजेंटिव सांसद सर डेविड डेविस ने कहा कि उनके महान मित्र फोर्सिथ एक शानदार व्यक्ति और शानदार शब्दकार थे। उन्होंने स्काई न्यूज से कहा-वे पुराने मूल्यों में बहुत विश्वास करते थे। वे सम्मान, देशभक्ति, साहस, सीधेपन और सरलता में विश्वास करते थे। वह हमारे सशस्त्र बलों के एक बड़े रक्षक थे। उनकी पहली पत्नी कैरोल कनिंघम से दो बेटे हैं। उनकी दूसरी पत्नी सैंडी मेलोय का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिका में भारतीय छात्र के साथ बदसलूकी, जमीन पर लाटाय़ा और बांधे हाथ-पैर



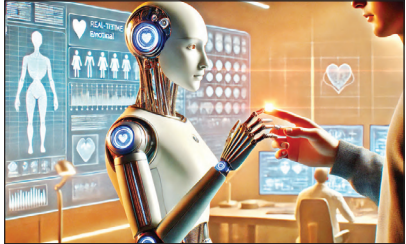
वॉशिंगटन। भारतीय छात्र को न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने पेट के बल लिटा रखा है और उसके हाथ और पैर बांध दिए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही लोग भड़के हुए थे। भारतीय छात्र के साथ अपराधियों जैसे बर्ताव का यह वीडियो मोके पर मौजूद और भारतीय-अमेरिकी कारोबारी कुणाल जैन ने बनाया था। अब इस मामले में न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास का बयान आया है। बता दें कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर विदेशी छात्रों और कर्मचारियों के वीजा रद्द किए जा रहे हैं। यह फैसला प्रशासन बिना बताए अचानक ही ले रहा है। कई बार फिलिस्तीन का समर्थन भी इसकी वजह बनता है। इसके अलावा कानून-व्यवस्था के नाम पर भी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। दूतावास ने टवीट किया, हमने सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट देखी हैं। इनमें दावा किया गया है कि एक भारतीय को नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परेशानी झेलनी पड़ी। हम स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं। भारतीयों के हितों की सुरक्षा के लिए कौसुलेट तत्पर है। छात्र के वायरल वीडियो में दिखाता है कि उसे दो अधिकारियों ने पकड़ रखा है और पेट के बल लिटा रखा है। वहीं दो अन्य अधिकारी उसके हाथों और पैरों को बांध देते हैं। इस दौरान भारतीय छात्र मदद की अपील करता सुनाई देता है। छात्र को अमेरिकी प्रशासन ने अवेध रूप से देश में आने के आरोप में पकड़ा था और उसे भारत वापस भेज दिया गया कुणाल जैन ने एक्स पर लिखा, मैंने देखा कि एक युवा भारतीय छात्र को नेवार्क एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जा रहा है। बीती रात ऐसा हुआ।

बाइडेन पर तंज कसने वाले ट्रंप अब खुद भी लड़खड़ने लगे ,सोशल मीडिया पर लोग ले रहे मजे



वॉशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्र और गिरने की आदत पर तंज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद उसी स्थिति में फंस गए हैं। दरअसल बाइडेन कई बार एयरफोर्स वन पर चढ़ने के दौरान लड़खड़ा चुके हैं। अब ट्रंप भी एयरफोर्स वन में चढ़ते वक्त लड़खड़ा गए और सोशल मीडिया पर फिर चर्चा का विषय बन गए। ये वाक्या अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के हेग्सटाउन में हुआ, जब ट्रंप वॉशिंगटन डीसी के पास स्थित पेपे डेविड के लिए रवाना हो रहे थे। तभी एयरफोर्स वन की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनका संतुलन बिगड़ा और वे लड़खड़ा गए। ट्रंप के तुरंत बाद विमान में चढ़ते वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ठोकर खा बैठे। इसके बाद लोगों ने पूरी घटना को बाइडेन से जोड़ दिया। दिलचस्प बात ये है कि ट्रंप और उनके समर्थक अक्सर बाइडेन के इसतरह के पतलों पर मजाक उड़ाते रहे हैं। लेकिन इस बार खुद ट्रंप सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए।

ज्यादा बुद्धिमान होकर रोबो, आने वाले सालों में इसानों को गुलाम बना देगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस



वॉशिंगटन। हाल ही में तकनीकी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अगले कुछ वर्षों में इसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकती है। यह विचार कई प्रमुख वैज्ञानिकों और तकनीकी नेताओं द्वारा वापस किया गया है, जिसमें एलन मस्क और रे कुर्ज़वील शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक स्टडी में 8,590 वैज्ञानिकों, उद्यमियों और समुदायों के विचारों के आधार पर यह निकर्ष निकाला गया है कि जल्दी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार कदम आगे निकलकर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) में बदल जाएगा। अगर आप नहीं समझे, तब सीधे तौर पर इसान से ज्यादा स्मार्ट बनकर उन्हें गुलाम बना लेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल यानि 2026 में एजीआई का आगमन हो सकता है। हालाकि कुछ उद्यमियों का कहना है कि कि साल 2030 के दशक में एजीआई संभव हो सकता है। वहीं वैज्ञानिक कहते हैं कि अगले 15 सालों में ये हो सकता है।

अगली ईरान-अमेरिका परमाणु वार्ता रविवार को मस्कट में, नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर 40 मिनट तक बात की

तेहरान/तेल अवीव/वॉशिंगटन, 10 मई (एजेंसियां) ।

ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अगली अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता ओमान की राजधानी मस्कट में होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए परामर्श के बाद तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता का अगला दौर रविवार को मस्कट में निर्धारित किया जा रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत की है।

ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बाघई ने सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के परमाणु उद्योग के लिए गैरनिर्णायक आवश्यकता है। यह स्वदेशी तकनीक ईरानी वैज्ञानिकों ने दशकों के सतत प्रयास के माध्यम से विकसित की है। अमेरिका के साथ होने वाली वार्ता या समझौते में यह विषय शामिल नहीं होगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने में बाधक कोई भी प्रस्ताव अस्वीकार्य होगा। ईरान जल्द ही ओमान के माध्यम से अपना प्रस्ताव सामने रखेगा। बाघई ने कहा कि अमेरिकी पक्ष इस अवसर को बर्बाद न करे। इस वार्ता को गंभीरता से ले। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और ईरान ने 12 अप्रैल से परमाणु वार्ता के पांच दौर आयोजित किए हैं। अब तक दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। दोनों देश यूरेनियम संवर्धन के स्तर को लेकर असहमत हैं।

इस बीच ईरान की सरकार न्यूज एजेंसी इरना ने कहा है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी कर चेतावनी दी है कि अगर इजराइली शासन इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई करता है तो ईरान उसके गुप्त परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमला करेगा। काउंसिल ने कहा है कि इजराइली के यह केंद्र उसके सशस्त्र बलों की मेज पर हैं। ईरान की सेना इजराइल को हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इस चेतावनी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू ने कल संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की।

खबर के अनुसार, नेतन्याहू और ट्रंप ने 40 मिनट



लॉस एंजिल्स में बढ़ रहा है आक्रोश, ट्रंप की नहीं सुन रहे प्रदर्शनकारी

लॉस एंजिल्स। अमेरिकी सरकार के प्रवासियों पर एवशन के बाद से शुरू हुई विरोध प्रदर्शन की आग अब और उग्र हो गई है। इस बीच ट्रंप के नेशनल गार्ड्स को उतारने के फैसले ने आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यहां और 700 मरीन की अस्थायी तैनाती का आदेश दिया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ अब और भी सख्ती से निपटा जाएगा। ट्रंप ने सोमवार को कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजोम को गिरफ्तार करने के धमकी भी दी है। गवर्नर गेविन न्यूजोम ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने और इसे लापरवाही भरा फैसला बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 2,000 जवान उन्हें खाना और पानी भी नहीं दिया गया। सिर्फ 300 जवान तैनात हैं, बाकी बिना किसी आदेश के बिल्डिंग में बैठे हैं। यह सुरुआ के लिए नहीं किया जा रहा है। यह फैसला एक राष्ट्रपति के अहंकार से जुड़ा है। न्यूसम ने कहा कि ट्रंप की ऐसी हरकतें तनाव को कम करने के बजाय बढ़ावा दे रही हैं। लॉस एंजिल्स में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन लगातार चोथा दिन था। यहां प्रवासियों को कैद कर रखे जाने वाले एक डिस्टेंशन सेंटर के आगे सैकड़ों लोग जमा हो गए। लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने बाहर के प्रमुख हाइवे को भी जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने डाउनटाउन में प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के आसू गैस के गोले और रबर की गोलियां चलाईं। इन सब के बीच कैलिफोर्निया राज्य ने सोमवार को नेशनल गार्ड और मरीन की तैनाती के खिलाफ लिए ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है। राज्य ने कहा है कि जवानों की तैनाती संघीय कानून और राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन करती है।

तक फोन पर बातचीत की। बातचीत के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने तेहरान के साथ वॉशिंगटन की चल रही परमाणु वार्ता पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री को बताया कि अमेरिका ने ईरान के समक्ष एक उचित प्रस्ताव रखा है और आने वाले दिनों में उसका जवाब

मिलने की उम्मीद है। बयान में इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया कि नेतन्याहू ने बातचीत के दौरान ट्रंप से क्या कहा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि बातचीत बहुत अच्छी रही। हम दोनों ने परमाणु वार्ता सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका की गुरुवार को ईरान के साथ बैठक है।

प्राकृतिक वातावरण में मिल सकता है शारीरिक दर्द से राहत: शोध



प्रकृति के बीच समय बिताने से पुराने पीढ़ी दर्द में काफी हद तक राहत मिल सकती है। यह दावा किया है एक ताजा शोध में। ब्रिटेन के प्लायमउथ विश्वविद्यालय द्वारा किए गए इस अध्ययन में बताया गया है कि जो लोग जंगल या किसी प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं, उन्हें न केवल अपने शारीरिक दर्द से राहत मिलती है बल्कि मानसिक तनाव और चिंता से भी छुटकारा मिलता है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 10 ऐसे लोगों का साक्षात्कार लिया जो कई वर्षों से पीढ़ी दर्द से जूझ रहे थे। इनमें से कुछ मरीज ऐसे भी थे जिन्हें यह समस्या चार दशकों से थी। जब उनसे पूछा गया कि वे अपने दर्द को कम करने के लिए क्या उपाय करते हैं, तो कई प्रतिभागियों ने बताया कि प्रकृति में समय बिताना उन्हें बेहद सुकून देता है। वे पेड़-पौधों के बीच टहलते हैं, ताजी हवा का आनंद लेते हैं और बहते पानी की आवाज से मानसिक शांति महसूस करते हैं। इससे उन्हें घर के बंद माहौल से बाहर निकलने और अकेलेपन से बचने का मौका भी मिलता है। शोध में शामिल लोगों ने यह भी बताया कि बाहर टहलने से उन्हें व्यायाम करने में आसानी होती है और यह उन्हें किसी जिम या व्यायामशाला से ज्यादा पसंद आता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि लंबे समय से चले आ रहे पुराने पीढ़ी दर्द के इलाज में यह एक प्रभावी और सहज उपाय हो सकता है।

पीएम मेलोनी कर रही विरोध, प्रस्ताव हुआ पास तो भारतीयों को होगा फायदा

रोम, 10 जून (एजेंसियां) ।

इटली में जनमत संग्रह शुरू हुआ है, जिसमें नागरिकता के नियमों को आसान बनाने और मजदूरों के अधिकारों को मजबूत करने से जुड़े पांच प्रस्तावों पर जनता की राय ली जा रही है। बता दें इटली की मौजूद सरकार इन मुद्दों के खिलाफ है और लोगों से अपील कर रही है कि वह इस जनमत संग्रह में हिस्सा ना लें। आमतौर पर लोग विदेशों में जाकर बसना चाहते हैं। इसमें वहां के कानूनों का

बड़ा रोल होता है। इटली में इस कानून को बदलने को लेकर जनमत संग्रह कराया जा रहा है। अगर ये पास होता है, तो इटली में बसने का लाखों भारतीयों का सपना पूरा हो जाएगा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की सरकार इन दोनों मुद्दों के खिलाफ है और लोगों से जनमत संग्रह में भागीदारी नहीं करने की अपील कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में कोई भी गैर-यूरोपीय नागरिक, जो न तो इटली की रिश्तेदार है और न ही वहां शादी के जरिए जुड़ा है। अब तक उसे इटली की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले देश में 10 साल रहना जरूरी होता है। इस जनमत संग्रह का प्रस्ताव इस अवधि



अमेरिकी संगीतकार स्ली स्टोन का 82 वर्ष की आयु में निधन

लॉस एंजिल्स, 10 जून (एजेंसियां) ।

अमेरिकी संगीतकार स्ली स्टोन (पूरा नाम साइवरस्ट स्टोन) का 82 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया। स्ली एंड द फैमिली स्टोन फंक बैंड समूह नेता स्टोन काफी समय से सीओपीडी (क्रॉनिक ऑक्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीनी) और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के बीच अंतिम सांस ली।

खबर के अनुसार, उनके बैंड ने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में धूम मचाई। स्ली स्टोन को 1969 में वुडस्टॉक संगीत समारोह में शानदार प्रदर्शन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इस समारोह में उन्होंने अपने फंक और हिप्पी संस्कृति से प्रेरित संगीत का प्रदर्शन किया। स्ली स्टोन ने फंक, ग्रूव और सिकोपेटेड लय से संचालित संगीत की अफ्रोकी-केंद्रित शैली को लोकप्रिय बनाने में मदद की। अमेरिकी संगीतकार स्ली स्टोन ने कई पीढ़ियों को डॉसफ्लोर पर थिरकने को मजबूर कर दिया। 1943 में टेक्सास में एक पेंटेकोस्टल धार्मिक परिवार में सिल्वेस्टर स्टीवर्ट के रूप में जन्मे स्टोन सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में पले-बढ़े उनका पहला संगीत तीन भाई-बहनों, स्टीवर्ट फोर के साथ एक गॉसल चोकडी में आया। इसे 1952 में स्थानीय रूप से रिलीज किया गया। 1966 में उन्होंने अपने बैंड स्ली एंड द स्टोन्स को अपने भाई फ्रेडी के ग्रुप फ्रेडी एंड द स्टोन सोल्स के साथ मिलाकर स्ली एंड द फैमिली स्टोन का



गठन किया। अगले वर्ष उन्हें डॉस टू द म्यूजिक के साथ सफलता मिली। तीन वर्ष बाद 1969 में उनका चौथा एलबम, स्टैंड आया। इसकी तीन मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं। उन्हें 1983 में कोकोन रखने और 1987 में कोकीन के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उनका जीवन गुमनामी में बीता। उन्होंने 2010 के कोचेला उत्सव में एक नीस उपस्थिति दर्ज कराई। उनका अंतिम एलबम आई एम बैक है। 2015 में उन्हें

अपने पूर्व प्रबंधक और वकील के खिलाफ एक मुकदमे में 5 मिलियन का डालर रॉयल्टी के रूप में हासिल हुए। परिवार के बयान में कहा गया, स्ली एक स्मारकीय व्यक्ति, एक अभूतपूर्व नववर्तक और एक सच्चे अग्रणी थे जिन्होंने पॉप, फंक और रॉक संगीत के परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया। गार्डियन के साथ 2023 के साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा खुशी होती थी अगर कोई मेरे काम को पसंद करता है।

को घटाकर पांच साल करना चाहता है, ताकि इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की तरह बन सके।

इस बदलाव से इटली में रहने वाले करीब 25 लाख बाहरी लोगों को फायदा मिल सकता है। साल 2023 में 2.13 लाख से ज्यादा लोगों को इटली की नागरिकता मिली, जो 2020 की तुलना में दोगुना है और पूरे यूरोपीय संघ में हुई नागरिकताओं का पांचवा हिस्सा है। इनमें से 90 फीसदी लोग यूरोपीय संघ के बाहर से थे, जो खासकर अल्बानिया, मोरक्को, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से आए।

इटली की पीएम मेलोनी की दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली अवैध आप्रवासन को रोकने के प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि

मौजूदा नागरिकता कानून बेहद उदार और अच्छा है। इटली पहले से ही हर साल यूरोप में सबसे ज्यादा लोगों को नागरिकता देता है, ऐसे में इसमें सुधार की कोई जरूरत नहीं है। मार्च 2025 में सरकार ने यह भी तय किया कि जो लोग अपने इतालवी वंश के आधार पर नागरिकता मांगते हैं, उनके लिए यह अधिकार अब सिर्फ दो पीढ़ियों तक सीमित रहेगा।

इस प्रस्ताव पर वोटिंग चल रही है, लेकिन इन प्रस्तावों के पास होने की संभावना कम है। इसकी वजह है जनमत संग्रह को वैध माने जाने के लिए 50 फीसदी से ज्यादा मतदान जरूरी है और अभी तक मतदान कम हुआ है। ये मुद्दा इटली की राजनीति और प्रवासी नीति, दोनों के लिए ही अहम है।



जीवन बीमा कंपनियों का नए प्रीमियम संग्रह 11 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, 10 जून (एजेंसियां)। चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में जीवन बीमा कंपनियों ने नए व्यवसाय से प्रीमियम संग्रह में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जीवन बीमा परिषद ने हाल ही में जारी आंकड़ों में बताया कि मई 2025 में नए व्यवसाय से प्रीमियम संग्रह में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

नए व्यवसाय से प्रीमियम आय मई 2025 में बढ़कर 30,463 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी महीने में 27,034 करोड़ रुपये थी। आंकड़ों से पता चलता है कि

वित्त वर्ष 2025-26 के पहले दो महीनों में संग्रह सालाना आधार पर 47,293 करोड़ रुपये से बढ़कर 52,427 करोड़ रुपये हो गया। मई 2025 में संयुक्त व्यक्तिगत प्रीमियम संग्रह में 3.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बताया गया है कि जीवन बीमा उद्योग में व्यक्तिगत एकल प्रीमियम में सालाना आधार पर 5.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह मई 2025 में 3,525 करोड़ रुपये रहा। देश की प्रमुख जीवन बीमा कंपनी एलआईसी का नए व्यवसाय से प्रीमियम मई 2025 में 10.27 प्रतिशत बढ़कर 18,405.04 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी महीने में 16,690.39 करोड़ रुपये था।

भारत बना साउथ ईस्ट एशिया का नया टूरिज्म हॉटस्पॉट

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्व एशियाई देश अब भारतीय पर्यटकों को लुभाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे देशों ने वीजा नियम आसान करने, प्रमोशनल कैपेन चलाने और भारतीयों के लिए खास टैवल पैकेज लॉन्च करने जैसे कई कदम उठाए हैं। एक वैश्विक यात्रा डाटा कंपनी के मुताबिक, मार्च 2025 तक की तय की गई उड़ानों के आंकड़े बताते हैं कि भारत और इन छह देशों के बीच सीटों की कुल उपलब्धता में 15.6 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। साल 2025 में इन देशों और भारत के बीच कुल 10.8 मिलियन सीटें उपलब्ध होंगी, कई देशों ने वीजा नियम किए आसान जो 2024 में मौजूद 9.35 मिलियन सीटों की तुलना में बढ़ी छलांग है। यह आंकड़ा न केवल एक नया रिकॉर्ड है, बल्कि यह कोविड-19 से पहले यानी 2019 की तुलना में भी 29 फीसदी अधिक है। थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश अब भी हवाई यात्रा की सीट क्षमता के लिहाज से भारतीय यात्रियों की शीर्ष पसंद बने हुए हैं, लेकिन वियतनाम ने हाल के वर्षों में जबरदस्त बढ़त दर्ज की है।

न्यूज़ ब्रीफ

आगामी दिनों में 20 रुपए तक बढ़ सकते हैं सीमेंट के भाव



नई दिल्ली। आगामी दिनों में सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं। बाजार के जानकारों के मुताबिक आगामी दिनों में सीमेंट के दाम 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनियां सीमेंट के दाम को लेकर जून के आखिरी तक फैसला ले सकती हैं। बाजार के जानकारों की मानें तो भारत में सीमेंट का कारोबार जनवरी से जून तक चरम में रहता है। इस दौरान मांग के अनुसार उत्पादन भी चरम पर रहता है। वहीं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक बारिश के दिनों में भवन निर्माण का काम मंदा रहता है। ऐसे में अनुमान है कि पूर्वी और दक्षिणी भारत की सीमेंट कंपनियां कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। हालांकि, अप्रैल और मई में की गई कीमत वृद्धि का कुछ हिस्सा जून में वापस लिया गया, लेकिन जून में एक और बढ़ोतरी की कोशिश हो सकती है।

पंजाब में बिजली की मांग 15,600 मेगावाट से अधिक पहुंची, इस बार बिजली की मांग जा सकती है 17,000 मेगावाट के पार



चंडीगढ़। पंजाब में भीषण गर्मी की वजह से बिजली की मांग 15,600 मेगावाट से ऊपर चली गई। इस बार धान की रोपाई का सीजन पिछले साल की तुलना में पहले शुरू हो गया है। तीसरे चक्र की धान की रोपाई शुरू हुई, इसके बाद चौथे चक्र की रोपाई शुरू होगी। दैर शाम करीब पौने सात बजे तक पंजाब में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया, जिससे एयर कंडीशनरों का उपयोग बहुत अधिक हो गया है। पिछले साल पंजाब में बिजली की सबसे अधिक मांग 16,069 मेगावाट दर्ज की गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार यह मांग 17,000 मेगावाट से भी पार जा सकती है। इस समय राज्य में लहरा मोहब्बत स्थित गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट का एक यूनिट बंद है, जबकि बाकी तीन यूनिट चालू हैं। इसी तरह रोपड़ स्थित गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट के सभी चारों यूनिट, गोइंदवाल साहिब के दोनों यूनिट, राजपुरा प्लांट के दोनों यूनिट और तलवंडी प्लांट के तीनों यूनिट बिजली उत्पादन में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त निजी बिजली परियोजनाओं से भी बिजली उत्पादन हो रहा है।

भारत में स्टारलिक के डिवाइस की कीमत 33,000 रुपए तक संभव, स्टारलिक की सेवा एक से दो महीने में शुरू होगी



नई दिल्ली। स्टारलिक भारत में जल्दी ही सेवाओं की शुरुआत करने वाली है। भारत में स्टारलिक के डिवाइस की कीमत 33,000 रुपये तक संभव है। सूत्रों के मुताबिक देश में स्टारलिक की सेवाएं अगले 1-2 महीने में शुरू हो सकती हैं। इसका असौमित डाटा प्लान 3000 रुपए से शुरू होगा। यही नहीं डिवाइस के साथ एक महीने का मुफ्त ट्रायल भी उपलब्ध होगा। स्टारलिक से दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की पहुंच संभव होगी। अन्य देशों की बात करें तो बांग्लादेश में स्टारलिक का न्यूनतम प्लान 2900 रुपए का है। यहां कंपनी 3000 में असौमित डाटा दे रही है। वहीं बांग्लादेश में स्टारलिक डिवाइस की कीमत 33,000 हजार रुपए है। इसी तरह भूटान में भी डिवाइस की कीमत 33,000 रुपए है। भूटान में असौमित डाटा पैक 3000 रुपए का है। स्टारलिक को भारत में सेवा देने के लिए दूरसंचार विभाग का लाइसेंस मिल गया है। अब उसे सिर्फ इंडियन नेशनल स्पेस मोशन एंड ऑर्थोराइजेशन सेंटर यानी, इन-स्पेस की स्वीकृति का इंतजार है।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत एशियाई बाजार में तेजी का माहौल

नई दिल्ली, 10 जून (एजेंसियां)।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए थे। हालांकि डाउ जॉन्स पन्थूचर्स बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजारों में आमतौर पर खरीदारी का जोर बना हुआ है।

अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार खरीदारी होती रही। हालांकि आखिरी वक्त में मुनाफा वसूली होने की वजह से वॉल स्ट्रीट के सूचकांक मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। डाउ जॉन्स पूरे दिन के कारोबार के बाद मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं एसएंडपी 500 इंडेक्स ने 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 6,005.88 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डैक 0.31 प्रतिशत उछल कर 19,591.24 अंक के स्तर पर बंद हुआ। डाउ जॉन्स पन्थूचर्स फिलहाल 134.06 अंक यानी 0.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 42,895.82 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली होती रही। एफटीएसई इंडेक्स 0.06 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 8,832.28 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 7,791.47 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 130.14 अंक यानी 0.54 प्रतिशत टूट कर 24,174.32 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में आमतौर पर मजबूती नजर आ रही है। एशिया के 9 बाजार में से 8 के सूचकांक बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि एक सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बना हुआ है। एशियाई बाजार में से इक्लैता स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.11 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 3,932.11 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 0.02 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 25,187 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह हेंग सेंग इंडेक्स 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,249.48 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। ताइवान वेटेड इंडेक्स ने जोरदार छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 424.81 अंक यानी 1.95 प्रतिशत उछल कर 22,215.10 अंक के स्तर तक आ गया है।



सरकार ने कृषि वस्तुओं को तीन श्रेणियों में बांटा

नई दिल्ली। भारत ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत कृषि वस्तुओं पर अपनी बातचीत में लक्ष्यण रेखाएं खींच दी हैं। इसके तहत भारत ने अपने कृषि उत्पादों को तीन श्रेणियों में बांट दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पहली श्रेणी में उन वस्तुओं को रखा गया है जिन पर कोई बातचीत नहीं हो सकती जबकि दूसरी श्रेणी में अत्यधिक संवेदनशील वस्तुओं को और तीसरी श्रेणी में उदारतापूर्वक विचार की जाने वाली वस्तुओं को रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह वर्गीकरण वस्तुओं की आर्थिक एवं राजनीतिक संवेदनशीलता के आधार पर किया गया है। चावल और गेहूं जैसी मुख्य खाद्य वस्तुओं को पहली श्रेणी में रखा गया है जहां शुल्क में किसी भी तरह की रियायत पर विचार नहीं किया जा सकता है। काफ़ी संवेदनशील वस्तुओं सेब आदि को रखा गया है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के किसानों के हितों से जुड़े हैं। इस श्रेणी की वस्तुओं पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) अथवा शुल्क दर कोटा के जरिये सीमित रियायतें दी जा सकती हैं। मगर भारत के अमीर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली महंगी वस्तुओं के आयात के मामले में सरकार उदार रुख अपना रही है जहां शुल्क में भारी छूट दी जा सकती है। इस श्रेणी में बादाम, पिस्ता, अखरोट, ब्लूबेरी आदि वस्तुएं शामिल हैं। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर इस साल के आखिर तक हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता जताई है। मगर भारत 9 जुलाई से लागू होने वाले अमेरिका के 26 फीसदी के जवाबी शुल्क से बचने के लिए जल्द से जल्द इस समझौते पर हस्ताक्षर करने पर जोर दे रहा है।



इसी तरह जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 1.31 प्रतिशत की मजबूती के साथ 7,206.79 अंक के स्तर तक पहुंच गया है। इसके अलावा निक्केई इंडेक्स 366.77 अंक यानी 0.96 प्रतिशत की बढ़त के साथ 38,455.34 अंक के स्तर पर, कोस्पी इंडेक्स 0.78

प्रतिशत की तेजी के साथ 2,878.05 अंक के स्तर पर, सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.28 प्रतिशत उछल कर 1,138.42 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,403.52 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

एवमे सोलर की राजस्थान में 75 मेगावाट सौर क्षमता शुरू



एवमे सोलर होल्डिंग्स ने राजस्थान के सीकर में अपनी 300 मेगावाट की सौर परियोजना में से 75 मेगावाट क्षमता शुरू कर दी है। कंपनी ने बयान में कहा कि एवमे सीकर सौर परियोजना में 165 मेगावाट क्षमता के चालू होने के बाद उर्वर क्षमता को चालू किया गया। एवमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ने अपनी सीकर परियोजना में अतिरिक्त 75 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता चालू की है, जिससे कुल चालू क्षमता नियोजित 300 मेगावाट में से 240 मेगावाट हो गई है। इसके साथ ही कंपनी की कुल परिचालन क्षमता बढ़कर 2,806.4 मेगावाट हो गई है।

पैसिल्वेनिया में डेटा सेंटर पर 20 अरब डॉलर खर्च करेगी अमेजन

हैरिसबर्ग, 10 जून (एजेंसियां)।

अमेरिका की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी अमेजन पैसिल्वेनिया में दो डेटा सेंटर परिसरों पर 20 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि इसमें से एक परिसर को उस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ बनाया जा रहा है जो ऊर्जा संयंत्र से सीधे जुड़ने की व्यवस्था को लेकर संघीय जांच के घेरे में है।

अमेजन की क्लाउड कंप्यूटिंग अनुष्णगी कंपनी अमेजन वेब सर्विसेज के वैश्विक डेटा सेंटर के उपाध्यक्ष केविन मिलर ने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को बताया कि कंपनी फिलाडेल्फिया के ठीक उत्तर में एक और डेटा सेंटर परिसर का निर्माण करेगी।

बयान में कहा गया है कि एक डेटा सेंटर उत्तरपूर्वी पैसिल्वेनिया के सुस्केहाना परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास बनाया जा रहा है, जहां से इसे



बिजली प्राप्त करने का इरादा है। दूसरा फेयरलेस हिल्स में एक लॉजिस्टिक्स कैंपस, कोस्टोन ट्रेड सेंटर में होगा जो कभी यूएस स्टील मिल हुआ करता था।

अमेजन ने कहा कि डेटा सेंटर को बिजली ग्रिड के माध्यम से बिजली मिलेगी। गौरतलब है कि कंपनी ने 2024 की शुरुआत से मिसिसिपी, इंडियाना, ओहायो और उत्तरी कैरोलिना में डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए लगभग 10-

टीवीएस मोटर ने टीवीएस अपाचे आरटीआर200 4वी की पेश

चेन्नई। दोपहिया एवं तिपहिया वाहन बनाने वाली टीवीएस मोटर कंपनी ने 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी मोटरसाइकिल श्रृंखला पेश की है। मोटरसाइकिल की नई श्रृंखला कंपनी की सभी डीलरशिप पर उपलब्ध है, जिसकी कीमत 1,53,990 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) से शुरू होगी है। यह ओबीडी2बी के अनुरूप है और उन्नत प्रौद्योगिकी, बेहतर प्रदर्शन एवं बेहतर सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। अपाचे मोटरसाइकिल श्रृंखला के 20 साल पुरे होने के मौके पर इसे पेश किया गया। टीवीएस मोटर कंपनी के प्रमुख ने कहा कि टीवीएस अपाचे ब्रांड सिर्फ एक मोटरसाइकिल के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक अभियान है जिसने दो दशकों में 60 लाख से अधिक राइडर्स के जोशीले समुदाय को प्रेरित किया है।



गोयल ने स्विट्जरलैंड में भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से मुलाकात की, नए निवेश अवसरों पर चर्चा

नई दिल्ली/बर्न, 20 जून (एजेंसियां)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों, साझेदारियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए स्विट्जरलैंड में भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने 'एक्स' पोस्ट पर जारी बयान में लिखा है कि, भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों के साथ एक आकर्षक शाम बिताई। भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उभर रहे भारत और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार और निवेश के लिए रोमांचक



अवसरों, साझेदारियों और नए अवसरों पर गहन चर्चा हुई। गोयल की यह बैठक उनकी दो

गोयल ने भारत-स्विट्जरलैंड आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए स्विस् उद्योग के साथ बातचीत की

दिवसीय स्विट्जरलैंड यात्रा का हिस्सा थी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी बयान में बताया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को स्विट्जरलैंड के बर्न में स्विस् उद्योग के नेताओं के साथ व्यापक बैठक की, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को गहरा करना और भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीडीपीए) के तहत नए रास्ते तलाशना था।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने विविध क्षेत्रों की कई प्रमुख स्विस् कंपनियों के नेतृत्व के साथ

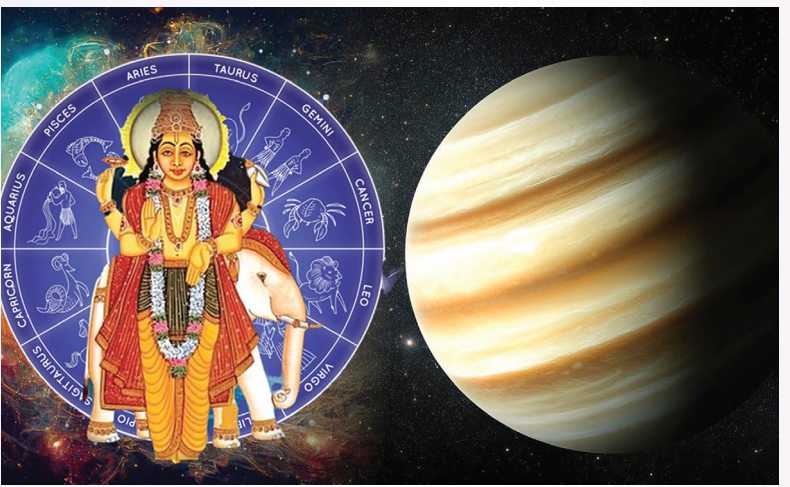
मुलाकात की, जिसमें भारतीय और स्विस् उद्यमों के बीच तालमेल बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और टिकाऊ विनिर्माण पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने स्विस् कंपनियों को भारत में अपना विस्तार करने और देश के गतिशील और तेजी से बढ़ते बाजार का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-ईएफटीए (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते ने भारत-स्विट्जरलैंड सहित ईएफटीए सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के नए द्वार खोले हैं। व्यापार प्रतिनिधियों के साथ पीयूष गोयल की चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौते का सर्वोत्तम लाभ कैसे उठाया जाए। वाणिज्य मंत्री गोयल 9 से 13 जून तक स्विट्जरलैंड और स्वीडन की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

देव गुरु बृहस्पति आज मिथुन राशि में होंगे अस्त

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है और यह ग्रह भाग्य, समृद्धि, ज्ञान और सम्मान का कारक होता है। गुरु ग्रह लगभग 1 साल में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, लेकिन इस वर्ष गुरु की गति सामान्य से दोगुनी होगी, जिससे वह एक वर्ष में दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है और अक्तूबर तक इसी राशि में रहेंगे। 11 जून को गुरु देव पश्चिम दिशा में अस्त होंगे। इसके बाद 7 जुलाई को पूर्व दिशा में उदय होंगे। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि 11 जून को गुरु देव पश्चिम दिशा में अस्त होंगे। इसके बाद 7 जुलाई को पूर्व दिशा में उदय होंगे। 6 जुलाई से चातुर्मास आरंभ हो जाएगा। जुलाई से चार महीना तक चातुर्मास रहेगा। इसमें मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी के बाद 21 नवंबर से विवाह आरंभ होंगे। विवाह में गुरु ग्रह को उदय होना आवश्यक माना जाता है। हमारे षोडश संस्कारों में विवाह का बहुत महत्व है। विवाह का दिन व लग्न निश्चित करते समय वर एवं वधु की जन्म पत्रिका अनुसार सूर्य, चंद्र व गुरु की गोचर स्थिति का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। जिसे त्रिबल शुद्धि कहा जाता है। विवाह के समय सूर्य वर की कन्य राशि से चतुर्थ, अष्टम या द्वादश गोचरवश स्थिति में नहीं होना चाहिए। गुरु कन्या की जन्मराशि से चतुर्थ, अष्टम या द्वादश एवं चंद्र वर-वधु दोनों की जन्मराशि से चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थित में नहीं होना चाहिए। यदि सूर्य, गुरु व चंद्र गोचरवश इन भावों में स्थित होते हैं, तब वे अपूज्य कहलाते हैं। शास्त्रानुसार ऐसी ग्रह स्थिति में विवाह करना निषेध बताया गया है।

ग्रहों के राजा सूर्य माने गए हैं। वहीं, मंत्री गुरु ग्रह हैं। गुरु ग्रह के साक्षी होने पर ही विवाह व मांगलिक कार्य होते हैं। 11 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। इस दिन शाम 6:54 बजे गुरु ग्रह पश्चिम दिशा में अस्त होंगे, लेकिन उससे पहले ही यानी 8 जून से ही शहनाईयां बजनी बंद हो जाएगी। गुरु ग्रह के अस्त होने के साथ सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष



जाएगा। जुलाई से चार महीना तक चातुर्मास रहेगा। इसमें मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी के बाद 21 नवंबर से विवाह आरंभ होंगे। ज्योतिष में गुरु ग्रह को संपन्नता, विवाह, वैभव, विवेक, धार्मिक कार्य आदि का कारक माना जाता है इसलिए इनका अस्त होना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए गुरु ग्रह जब अस्त होते हैं तब शुभ-मांगलिक कार्यों को करने की भी मनाही होती है, इस दौरान शादी, मुंडन, नामकरण जैसे संस्कार नहीं किये जाते।

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव

गुरु के अस्त होने का सबसे प्रतिकूल प्रभाव कर्क, धनु और मीन राशियों पर पड़ सकता है, इसलिए इन राशियों के लोगों को गुरु अस्त के दौरान गुरु ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए। बाजार पर भी गुरु के अस्त होने का प्रभाव दिखेगा। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। इन दिनों शेयर में बहुत ही ज्यादा संभलकर निवेश करने की जरूरत है।

कर्क, धनु और मीन राशि वालों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

गुरु अस्त होने से कर्क, मीन और धनु राशि वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस राशि वालों को कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए। साथ ही अभी कोई नया व्यापार भी शुरू नहीं करना चाहिए। वरना नुकसान हो सकता है। इस अवधि में नुकसान, शत्रुओं से हानि का सामना करना पड़ सकता है। वहीं किसी विवाद भी हो सकता है। लिहाजा इस समय बेहद

करें उपाय

गुरु के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए गुरु से संबंधित उपाय करने चाहिए। जैसे पीले वस्त्र आपको पहनने चाहिए या पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए हो सके तो इस दौरान प्रतिदिन आप योग ध्यान करें। इसके साथ ही केले के वृक्ष की पूजा करने से भी आपको लाभ मिल सकते हैं। बड़े फैसले अनुभवी लोगों से विचार करके लें।

गुरु अस्त होने का सभी 12 राशियों पर प्रभाव।

मेष राशि

आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। गुरु के अस्त होने से धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा। माता-पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनेगी।

वृषभ राशि

आपके घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर कहीं से धन आ रहा है को उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है।

मिथुन राशि

सामाजिक कार्यों को करने से आपका सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सफलता अवश्य मिलेगी।

कर्क राशि

अगर आप इस समय किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल के लिए उसे टाल दें। थोड़ा संभलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

सिंह राशि

अचानक आने वाली समस्याओं में कमी आएगी और व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी।

कन्या राशि

जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और कोई खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। अगर

आपका किसी से वाद-विवाद चल रहा है तो वह खत्म हो जाएगा। अच्छा लाभ होगा।

तुला राशि

धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अति आत्मविश्वासी होने से बचना होगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।

वृश्चिक राशि

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन गुरुजनों का सहयोग भी मिलता रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ आपके संबंध उतार-चढ़ाव वाले रहेंगे।

धनु राशि

सरकारी नौकरी करने वाले जातक अपने काम पर ध्यान दें अन्यथा किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। माता या पिता के साथ किसी बात टकराव हो सकता है।

मकर राशि

जीवनसाथी के साथ किसी गलतफहमी की वजह से विवाद हो सकता है। मकर राशि वालों को इस अवधि में थोड़ा संभलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

कुंभ राशि

बड़ा नुकसान हो सकता है। इस अवधि में परिवार के किसी सदस्य के कार्य की वजह से भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपके लिए इस दौरान बेहतर होगा कि अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें अन्यथा किसी विवाद में फंस सकते हैं

मीन राशि

कार्यक्षेत्र में आप अच्छे से काम करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। हालांकि इस दौरान आप कहीं भी निवेश करने से बचें और परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें।



डॉ. अनीष व्यास
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर
मो.9460872809

आषाढ़ अमावस्या पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, हो जाएंगे धनवान!



सनातन धर्म में आषाढ़ अमावस्या का दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन कई तरह के धार्मिक काम किए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल आषाढ़ अमावस्या 25 जून को मनाई जाएगी।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस तिथि पर दान-पुण्य और गंगा स्नान करने से जीवन में खुशहाली आती है। इसके साथ ही घर की दरिद्रता का नाश होता है। वहीं, इस दिन कुछ दान अवश्य करना चाहिए, जो इस तिथि का मुख्य अनुष्ठान भी माना जाता है।

आषाढ़ अमावस्या पर करें ये दान

मेष राशि: मेष राशि के लोगों को आषाढ़ अमावस्या पर लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए।

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातक को इस दिन पर सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए।

मिथुन राशि: मिथुन राशि के लोगों को इस तिथि पर हरे रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए।

कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों को आषाढ़ अमावस्या पर दही का दान करना चाहिए।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों को इस तिथि पर लाल चंदन का दान करना चाहिए।

कन्या राशि: कन्या राशि के लोगों को इस मौके पर साबुत उड़द का दान करना चाहिए।

तुला राशि: तुला राशि के लोगों को आषाढ़ अमावस्या पर चावल का दान करना चाहिए।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवसर पर गुड़ का दान करना चाहिए।

धनु राशि: धनु राशि के लोगों को इस दिन पर हल्दी का दान करना चाहिए।

मकर राशि: मकर राशि के लोगों को आषाढ़ अमावस्या पर सरसों के तेल का दान करना चाहिए।

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों को इस तिथि पर काली उड़द का दान करना चाहिए।

मीन राशि: मीन राशि वालों को इस मौके पर आम का दान करना चाहिए।

घर में लगाएं ये पौधे, पत्नी-पत्नी के बीच महकने लगेगा रिश्ता

पति-पत्नी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। कभी प्यार कभी तकरार। नॉक-ड्रॉक के बाद थोड़ी देर के लिए अलग भी हो जाएं, तो एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता है। क्या हो अगर आपके रिश्ते में नॉक-ड्रॉक के लिए कोई जगह ही न बचे। अगर कुछ वास्तु से संबंधित उपाय कर लें, तो आपके रिश्तों की गर्माहट हमेशा के लिए बनी रह सकती है। इसके लिए आपको अपने घर और बगिया को थोड़ा महकाना पड़ेगा। मगर, चिंता मत कीजिए इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और मेहनत भी नहीं लगेगी। हम आज आपको ऐसे ही कुछ पौधे बताते जा रहे हैं, जिनको घर में लगाने के बाद उनकी महक आपके रिश्ते को भी महकाती रहेगी। ये पौधे और इनमें लगने वाले फूल आगे घर का माहौल भी खुशनुमा बनाएंगे और सौभाग्य भी देने में मददगार साबित होंगे।

सदाबहार का पौधा –सदाबहार में गुलाबी और सफेद रंगों के फूल आते हैं, जो प्यार को बढ़ाने वाले और पॉजिटिविटी लाने वाले माने जाते हैं। सदाबहार का पौधा घर के पूर्व दिशा में लगाने से पति-पत्नी के बीच प्यार और विश्वास बढ़ता है।

जैसा इसका नाम है, वैसे ही यह पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। इसकी पॉजिटिव वाइब्स भी आपके प्यार को सदाबहार बनाए रखती है। नवविवाहितों के लिए सफेद फूल विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। ये मन को



सावन का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा

भगवान शिव के भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत महत्व रखता है। इस पूरे माह में भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और सोमवार के दिन व्रत रखने का विधान है। शिव भक्त इस पवित्र माह का पूरे साल इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं।

हिंदू पंचांग के आधार पर इस साल सावन माह 11 जुलाई, 2025 से शुरू होगा। वहीं, इसका समापन अगले महीने यानी 09 अगस्त, 2025 को होगा। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। वहीं, सावन का पहला व्रत 14 जुलाई, सोमवार के दिन रखा जाएगा।

सावन सोमवार व्रत लिस्ट

सावन पहला सोमवार 14 जुलाई 2025

सावन दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025

सावन तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025

सावन चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025

सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि

सावन के पहले सोमवार पर जल्दी उठें और स्नान करें। साफ कपड़े पहनें। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा की थाली तैयार करें और एक वेदी भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उनका विधिपूर्वक अभिषेक करें। बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, सफेद चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई, पंचामृत आदि चीजें चढ़ाएं। शिवलिंग पर भी गंगाजल और दूध चढ़ाएं। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें। सावन सोमवार व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। व्रत के दौरान तामसिक चीजों से दूर रहें और सिर्फ फलाहार के रूप में फल, दूध, दही, साबूदाना, कुड़ू का आटा, सेंधा नमक आदि का सेवन कर सकते हैं। व्रत के समापन के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को दान-दक्षिणा दें।



जगन्नाथ यात्रा के दौरान घर लाएं ये चीजें, मिलेगा अपार धन और यश

हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत महत्व है। यह हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निकाली जाती है। इस साल यह धर्म यात्रा 27 जून, शुक्रवार को शुरू होगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इसमें शामिल होने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं, इस यात्रा से कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें जरूर लाना चाहिए।

रथ यात्रा के दौरान घर लाएं ये चीजें

निर्माण्य – पुरी में भगवान जगन्नाथ का विशेष प्रसाद, जिसे निर्माण्य कहा जाता है। ये एक तरह के सूखे चावल होते हैं। यह महाप्रसाद जगन्नाथ मंदिर के कोइली बैकुंठ के अंदर तैयार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे घर लाने और ग्रहण करने से सभी पाप कट जाते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

रथ की लकड़ी का छोटा टुकड़ा – जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ नीम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद इन रथों की लकड़ियों के कुछ अंश भक्तों को दिए जाते हैं। कहते हैं कि रथ की लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा घर में लाने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके साथ ही घर में सुख-



शांति बनी रहती है।

भगवान जगन्नाथ की तस्वीर – अगर आप रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाएं हैं, तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की एक छोटी प्रतिमा या तस्वीर घर लेकर आएँ और नियमित रूप से उनकी पूजा करें। इससे भगवान की कृपा मिलेगी। साथ ही सभी दुख दूर होंगे।

महाप्रसाद – पुरी मंदिर का महाप्रसाद, जिसे अन्न ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। इस महाप्रसाद को घर लाने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं।

तुलसी की माला – भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के ही रूप हैं और तुलसी उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसे में रथ यात्रा के दौरान पुरी से तुलसी की माला जरूर लाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।



65 की उम्र में भी थिएटर में दहाड़ रहे हैं साथ अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण



अक्सर सेलिब्रिटी स्क्रीन पर सपोर्टिंग रोल करने लगते हैं लेकिन वहीं एक साथ में कई ऐसे अभिनेता हैं जो ढलती उम्र में एक्शन करते दिखते हैं। यहां हम एक ऐसे ही अभिनेता के बारे में बात कर रहे हैं जो 65 की उम्र में बैक-टू-बैक फिल्में कर रहे हैं। और आज उनका 65वां जन्मदिन है।

दरअसल, 60 क्रॉस करने के बाद अगर कोई भी हीरो एक्शन स्टंट कर सकता है, लेकिन उन्हें अहा लगता है तो वो बलैया है। स्क्रीन पर बलैया यानी नंदामुरी बालकृष्ण को देखकर ही छोटे

बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को वाइब आ जाती है। फिल्म कोई भी हो, बलैया का नारा कॉमन है। दरअसल, मौजूदा सीनियर हीरो के बीच बलैया का स्तर अलग है। जब उनकी फिल्म आती है तो माहौल सामान्य नहीं होता। खास तौर पर बच्चों को बलैया की फिल्में उतनी पसंद नहीं आतीं, जितनी हमेशा आती हैं।

ढलती उम्र में भी वे सीटियों और जयकारों से थिएटरों को हिला देते हैं। बलैया, जिसकी कभी कुछ करोड़ की मार्केट नहीं थी, अब पहले दिन 50 करोड़ रुपये कमाकर अपनी प्रतिभा का

लोहा मनवा रहा है। बलैया की असल लाइनअप को देखकर लगता है कि इसमें कोई हाइप नहीं है। आज बलैया का 65वां जन्मदिन है। इस मौके पर फिल्मी हस्तियों से लेकर राजनीतिक नेता तक अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जब बात सेलिब्रिटीज की आती है तो फैस उनसे जुड़ी हर बात जानने में दिलचस्पी रखते हैं। उनके शौक क्या हैं? वे क्या खाते हैं? उन्होंने क्या पढ़ा है? ऐसी बातें जानने में उनकी दिलचस्पी है। बलैया के प्रशंसक जगजाहिर हैं। इसलिए उनके प्रशंसक यह जानने में रुचि रखते

हैं कि बलैया ने क्या पढ़ा है। वैसे, बलैया ने उस समय अपनी डिग्री हासिल की थी। उन्होंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स में अपनी डिग्री पूरी की।

अब भले ही यह कोई बड़ी बात न हो, लेकिन।।। उस समय, जब वे फिल्मों में व्यस्त कलाकार थे, उन्होंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी डिग्री पूरी की। उन्हें वास्तव में डिग्री की जरूरत नहीं थी। लेकिन।।। उन्होंने अपने पिता की बात का सम्मान किया और इसे पूरा किया। बात अगर वर्कफ्रंट

को लेकर करें तो फिलहाल, बलैया के हाथ में दो फिल्में हैं। वे बोयापति श्रीनु के निर्देशन में एक सीकल बना रहे हैं जिसका टाइटल अखंड 2 है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है जिसने इसके रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दूसरी ओर, बलैया गोपीचंद मालिनेनी के निर्देशन में अपनी 111वीं फिल्म बना रहे हैं, जिन्होंने वीरसिम्हा रेड्डी के साथ बलैया के प्रशंसकों को भरपूर भोजन दिया था।

आशिक अरबपति पर सना सुल्तान ने कहा दर्शकों को पसंद आएगी मेरी कहानी



अभिनेत्री सना सुल्तान को एलटीटी की नई वर्टिकल सीरीज कुटिमस के लिए चुना गया है। सना कुटिमस यूनिवर्स के एक एपिसोड 'आशिक अरबपति' में नजर आएंगी। सीरीज के बारे में अपने विचार को व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि यह महिला के व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं पर आधारित है। दर्शकों को यह कहानी जरूर पसंद आएगी। सीरीज के बारे में सना ने बताया, कुटिमस एक वर्टिकल ड्रामा सीरीज है। यह एक खूबसूरत फॉर्मेट है, जिसमें रोमांच, रहस्य, भावनाएं, प्यार, नफरत सब कुछ छोटे-छोटे एपिसोड में समाहित हैं।

फॉर्मेट के बारे में अपनी पसंद को जाहिर करते हुए उन्होंने बताया, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, वह यह है कि इतने कम समय में बहुत कुछ अनुभव करने या सीखने को मिला। यह एक बहुत ही रोमांचक कॉन्सेप्ट है और मुझे विश्वास है कि लोग इसे पसंद करेंगे और इससे जुड़ाव महसूस करेंगे।

सना ने आगे बताया, मेरी कहानी में आप सब कुछ देख सकेंगे। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है, जिसके दो पक्ष हैं। वह एक तरफ तो नरम है, वहीं दूसरी ओर सख्त भी है। मैं यह कह सकती हूं कि मेरी कहानी बहुत ही शानदार और दर्शकों को पसंद आने वाली है और एक महिला के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को छूती है।

सना ने खुलासा किया कि जब उन्हें यह ऑफर हुआ तो उन्होंने बिना देरी किए झट से हां कह दिया था। उन्होंने बताया, खुद एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मैं रील और शॉर्ट-फॉर्म वीडियो के क्रेज को समझती हूं। इसलिए, मुझे इसकी खूबियों के बारे में अच्छी तरह से पता था। सना ने कहा, लोग इसे देखेंगे तो पसंद करेंगे। क्योंकि, इसकी कालिटी और स्टोरी दोनों बेजोड़ हैं। यह घर पर शूट किया गया एक रील नहीं, यह एक अच्छी तरह से निर्मित शो है, जो एक छोटे, वर्टिकल फॉर्मेट में एक फिल्म देखने जैसा अनुभव देगा।

मालिक की धड़कन बनीं मानुषी छिल्लर

मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर अपनी अगली फिल्म मालिक में एक ऐसी भूमिका में नजर आने वाली हैं, जो पहले कभी नहीं देखी गई है। 11 जुलाई को रिलीज होने वाली इस बहुप्रतीक्षित गैंगस्टर ड्रामा के निर्माताओं ने आखिरकार फिल्म में मानुषी छिल्लर का लुक जारी कर दिया है। एक साधारण लेकिन पारंपरिक भारतीय पोशाक में सजी मानुषी इस पोस्टर में बेहद सौम्य, खूबसूरत और शांली नजर आ रही हैं, और उनके साथ लीड एक्टर राजकुमार राव भी दिखाई दे रहे हैं। मानुषी ने अपने ग्लैमरस व्यक्तित्व से हट कर एक साधारण और पारंपरिक लुक अपनाया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फिल्म का निर्देशन पुलकित ने किया है और इसे कुमार तारानी और जय

शेवकरमणि ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में मानुषी को एक ऐसे किरदार में दिखाया गया है, जिसे उन्होंने अभी तक बड़े पर्दे पर नहीं निभाया है।

इस फर्स्ट लुक के जरिए मानुषी न सिर्फ चौंकाती हैं, बल्कि हमें प्रभावित भी करती हैं! वह मालिक के साथ अपनी पिछली ऑन-स्क्रीन प्रस्तुतियों और भूमिकाओं से एक सूक्ष्म बदलाव करती हैं, इस प्रकार इंडस्ट्री में वो खुद को एक बहुमुखी कलाकार के रूप में गंभीरता से लिए जाने की उनकी महत्वाकांक्षा का संकेत देती हैं। 'मालिक की धड़कन' के रूप में पेश किए गए पोस्टर में मानुषी और राजकुमार की जोड़ी बेहद आकर्षक लग रही हैं। राजकुमार राव ने मानुषी के किरदार का परिचय देते हुए लिखा, जिनके बिना चलती नहीं



मालिक की धड़कन, उनसे होगी आज मुलाकात जहां पोस्टर में दोनों लीड किरदारों के बीच प्यार और

केमिस्ट्री की झलक मिलती है, वहीं चूंकि मालिक एक गहन गैंगस्टर ड्रामा है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही

हैं कि मानुषी की किरदार केवल एक पारंपरिक प्रेमिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें कई परतें होंगी। फिल्म में बंगाल के दिग्गज अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, अंशुमान पुष्कर और स्वराज किरकिरे जैसे दमदार कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। सूत्रों के अनुसार, मानुषी का किरदार फिल्म की कहानी में बेहद अहम है और मेकर्स इसकी डिटेल्स रिलीज से पहले उजागर नहीं करना चाहते। पोस्टर के नीचे कई नेटिजन्स ने मानुषी की सादगी की प्रशंसा करने से लेकर उनके आराम क्षेत्र को चुनौती देने वाली भूमिकाएं करने के लिए उनकी प्रशंसा करना शामिल है। मालिक की रिलीज के बाद, मानुषी अगली बार तेहरान में दिखाई देंगी, जहाँ वह जॉन अब्राहम के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करेंगी।

पारुल गुलाटी ने दोनाली के लिए लीड बंदूक चलाने की ट्रेनिंग, कहा

स्क्रीन पर दिखना चाहती हूं दमदार

अभिनेत्री पारुल गुलाटी ने अपने किरदार को असली और दमदार दिखाने के लिए बंदूक चलाने की कड़ी ट्रेनिंग ली। उन्होंने खास तौर पर 'देसी कट्टा' और 'डबल बैरल रायफल' जैसी बंदूकें चलाना सीखा, ताकि उनका किरदार स्क्रीन पर दमदार और प्रभावशाली लगे।

पारुल गुलाटी वेब सीरीज 'दोनाली' में एक डकैत का किरदार निभा रही हैं। अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, डकैत का रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल लेकिन मजेदार अनुभव रहा। मैं चाहती थी कि जब मैं बंदूक पकड़ूं और चलाऊं, तो वह स्क्रीन पर असली लगे और लोगों को मेरा किरदार सच्चा लगे।

उन्होंने आगे कहा, इस किरदार को निभाने के लिए सिर्फ एक्शन ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उसमें सही रवैया, चाल-ढाल और असलीपन दिखाना भी जरूरी होता था। देसी कट्टा और डबल बैरल रायफल चलाना सीखने से मुझे अपने किरदार को एक नया नजरिया मिला और मैं इसे पूरी तरह से बेहतरीन करना चाहती थी। पारुल सीरीज 'दोनाली' में नजर आएंगी। इस फिल्म में वह अभिनेता दिव्येंदु और बरुण सोबती के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।

सीरीज का निर्देशन ई निवास ने किया है। इसमें चंकी पांडे, यशपाल शर्मा और अन्य कलाकार भी अहम किरदार में हैं। इसकी कहानी 1960 के दशक में चंबल के बीहड़ इलाके की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में की गई है। पारुल गुलाटी एक उद्यमी और मॉडल भी हैं। उन्होंने कई टीवी शो और पंजाबी फिल्मों में काम किया है।



सपरिवार उज्जैन पहुंचीं अभिनेत्री कुनिका सदानंद, किए महाकाल के दर्शन

अभिनेत्री कुनिका सदानंद मंगलवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दरबार पहुंचीं, जहां उन्होंने महाकालेश्वर के दर्शन किए। अभिनेत्री के साथ उनका परिवार भी नजर आया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से अभिषेक शर्मा ने अभिनेत्री कुनिका का स्वागत किया। मंदिर पहुंची कुनिका नंदी हॉल में शिव साधना करती और नंदी पर जल अर्पित करती दिखीं। चांदी द्वार से माथा टेककर उन्होंने परिवार संग भगवान का आशीर्वाद लिया।

कुनिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1988 में आई फिल्म 'कब्रिस्तान' से की थी। उन्होंने 'बेटा', 'गुमराह' और 'खिलाड़ी' जैसी कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं। कुनिका ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। फिल्मों के अलावा, वह टीवी शो 'स्वाभिमान', 'काना फूसी', 'प्यार का दर्द है मीठा-मीठा प्यार-प्यार', 'अकबर बीरबल', 'दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स' में भी काम कर चुकी हैं। कम लोग ही जानते हैं कि वह अभिनेत्री के साथ ही बेहतरीन गायिका भी हैं। कुनिका सदानंद से पहले 'केजीएफ' फेम साथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश भी महाकाल के दर्शन को उज्जैन पहुंचे थे। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती लोकप्रिय है और इसमें शामिल होने के लिए दुनियाभर से श्रद्धालु उज्जैन आते हैं।



दीपिका पादुकोण देशभर में खोलेंगी पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन के 75 नए सेंटर

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, उतनी ही अच्छी बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी हैं। बता दें कि वह नेशनल लेवल पर बैडमिंटन खेल चुकी हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि वह बचपन से ही बैडमिंटन खेलते हुए बड़ी हुई हैं। इस खेल ने उनकी जिंदगी को नया आकार दिया है। ऐसे में वह चाहती हैं कि और लोग भी इस खेल से जुड़ें, इसके लिए उन्होंने पूरे देश में 'पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन' के 75 नए सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अपने पापा प्रकाश पादुकोण के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। उनके पापा बैडमिंटन के जाने-माने खिलाड़ी रह चुके हैं।

इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, मैंने बचपन में बैडमिंटन खेला है, और मैंने खुद

महसूस किया है कि यह खेल इंसान की जिंदगी को कई तरीकों से बदल सकता है, शारीरिक, मानसिक और भावनाओं से भी। दीपिका ने बताया कि 'पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन' (पीएसबी) के 75 नए सेंटर देशभर में खोले जा रहे हैं। पीएसबी के जरिए हम चाहते हैं कि बैडमिंटन की खुशी और अनुशासन हर क्षेत्र के लोगों तक पहुंचे। हमारा मकसद है कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो, जो सेहतमंद हो, ध्यान से काम करे और खेलों से प्रेरित हो। प्रेस नोट में लिखा, पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन (पीएसबी), जिसकी शुरुआत दीपिका पादुकोण ने की है और इसे उनके पिता प पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण मार्गदर्शन दे रहे हैं, ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पीएसबी अपने पहले ही साल में भारत के 18 शहरों में 75 से ज्यादा कोचिंग सेंटर

शुरू करने जा रहा है। इन शहरों में बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, पुणे, नासिक, मैसूर, पानीपत, देहरादून, उदयपुर, कोयंबटूर, सांगली और सूरत जैसे शहर शामिल हैं।

प्रेस नोट में आगे कहा गया, 'बैडमिंटन फॉर ऑल' के मिशन के साथ, पीएसबी का लक्ष्य है कि साल के अंत तक 100 सेंटर और अगले तीन सालों में 250 सेंटर तक पहुंचा जाए।

नोट में आगे कहा गया, अकादमी का मकसद है कि अच्छी और किफायती बैडमिंटन कोचिंग हर किसी को मिल सके, चाहे वह किसी भी उम्र का हो। प्रकाश पादुकोण के मार्गदर्शन में बनाई गई कोचिंग पद्धति के जरिए, यह संस्था देश भर के स्कूल के बच्चों और कामकाजी लोगों को बैडमिंटन से जोड़ना चाहती है। साथ ही, यह उन लोगों को भी मदद देना चाहती है जो बैडमिंटन

कोच बनना चाहते हैं, ताकि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग और एक स्थिर करियर मिल सके।

नोट में आगे लिखा गया, 'पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन' स्कूलों, संस्थाओं और पहले से मौजूद स्पोर्ट्स वेन्यू के साथ मिलकर छोटे-छोटे ट्रेनिंग सेंटर शुरू करता है। इन सेंटर से चुने गए अच्छे खिलाड़ी बेंगलुरु में मौजूद इसके तीन बड़े हार्ड-परफॉर्मेंस सेंटर में एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं।

100 से ज्यादा कोचों को एक खास ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। साथ ही, पीएसबी के पास सबसे आधुनिक सुविधाएं हैं। इससे उनकी कोचिंग में एक जैसा तरीका और अच्छी कालिटी बनी रहती है, और वह आने वाले समय के चैंपियन खिलाड़ियों को पहचानकर उनकी मदद कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना बनी वरदान

नीतीश सरकार की पहल से हजारों मासूमों को मिली संजीवनी

पटना (एजेंसियां)।

‘मेरा बच्चा मासूम है, उसके हृदय में छेद है, मेरे पास इतने पैसे कहां हैं, जो इसका इलाज करा पाऊंगी।’ ऐसे लाचार शब्द अब बिहार में बीते दिनों की बात हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना ने न सिर्फ मासूम बच्चों को नया जीवन दिया है, बल्कि कई टूटते घरों को फिर से संजीवनी दी है।

राज्य सरकार की इस योजना के तहत बिहार में हृदय रोग से पीड़ित 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क उपचार और शल्य चिकित्सा कराई जाती है।



वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 763 बच्चों का सफल ऑपरेशन हो चुका है। अब ये बच्चे सामान्य जीवन जी रहे हैं और उनके घरों में एक बार फिर से खुशियां लौट आई हैं।

मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत वर्ष 2021 से अब तक 1,828 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। इनमें से 1,391 बच्चों की सर्जरी अहमदाबाद स्थित श्री सत्य साई

हृदय अस्पताल में कराई गई। योजना की शुरुआत 5 जनवरी, 2021 को सात निश्चय पार्ट 2 के तहत की गई थी।

पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को विशेष केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।

अब तक राज्य में 9 स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें हजारों बच्चों की स्क्रीनिंग की गई।

इस योजना के तहत बच्चों की शुरुआती जांच, यात्रा खर्च, अस्पताल में भर्ती से लेकर ऑपरेशन तक का पूरा खर्च बिहार

सरकार वहन करती है। एक अध्ययन के मुताबिक हर 1,000 नवजात में से 9 बच्चे जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, जिनमें से 25% को पहले वर्ष में सर्जरी की जरूरत पड़ती है।

जल्द ही 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को भी इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी, जो दिल में छेद की बीमारी से ग्रसित हैं। इसके लिए श्री सत्य साई हृदय अस्पताल, अहमदाबाद में इलाज की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा।

नालंदा पुलिस को बड़ी सफलता

साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

नालंदा (एजेंसियां)।

नालंदा जिले के कतरीसराय थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव से साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यह गिरोह कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने और सस्ती ब्याज दर पर लोन फाइनेंस कराने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। नालंदा पुलिस ने चार साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नालंदा एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई। विशेष छापेमारी दल ने सोमवार को परमानंदपुर गांव में छापेमारी कर चार अभियुक्तों को पकड़ा।

पुलिस जांच में पता चला कि आलोक कुमार और राहुल कुमार



पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

आलोक पर गिरियक थाना में 2022 से 2024 तक धोखाधड़ी, जालसाजी और साइबर फ्राडम के तहत मामले दर्ज हैं। राहुल कुमार पर भी साइबर फ्राडम के केस दर्ज हैं।

इस अभियान में कतरीसराय थाना अध्यक्ष सत्यम तिवारी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की टीम शामिल थी, जिनमें दारोगा आदित्य कुमार, मुकुंद भारती, अनिल गुरुदेव खड़िया, प्रसेनजीत चौधरी, मनीष कुमार, स्वीटी सोरेन और अन्य शामिल रहे।

नशे के खिलाफ चला सघन अभियान

8 गिरफ्तार, भारी मात्रा में स्मैक और शराब जब्त

जहानाबाद (एजेंसियां)।

जहानाबाद शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों नशे का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है।

सुखा नशा और देसी शराब की खुलेआम बिक्री से जहां युवा पीढ़ी को नुकसान हो रहा है, वहीं पुलिस भी इसके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जहानाबाद में मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया।

सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में यह अभियान देर रात शहर के पंचमुहल्ला सहित



ने जानकारी दी कि यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी और आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस का रुख बेहद सख्त रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं

जाएगा।

स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगेगी। साथ ही पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसे नशा तस्करों का सामाजिक बहिष्कार करें और उनकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। गौरतलब है कि जहानाबाद में सुखा नशा की लत बच्चों और नौजवानों में तेजी से बढ़ रही है, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन इस दिशा में लगातार गंभीरता से प्रयासरत है।

लालू ने आंकड़े दिखा एनडीए सरकार पर बोला हमला

नीतीश-भाजपा ने विधि व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया

पटना (एजेंसियां)।

आगामी विधानसभा सभा चुनाव से पहले विपक्ष नीतीश सरकार को आंकड़े दिखाकर घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़े दिखाकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। अब उनके पिता और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एनडीए सरकार पर हमला बोला और कई आरोप भी लगा दिए।



राजद सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नीतीश बताएं कि शाम पांच बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी

हत्याएं हो रही है? क्या नीतीश जानते, पहचानते और समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं? 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। लालू प्रसाद ने आगे लिखा कि नीतीश-भाजपा ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी, कभी

भी नहीं रही।

तीन दिन पहले भी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला था। सात जून को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हैं। अफसरशाही मदमस्त हैं। सरकार बेहोश है और महंगाई रिकॉर्डतोड़ है। राज्य गरीबी, बेरोजगारी, पलायन बढ़ गई है। 20 वर्षों की इस एनडीए सरकार ने बिहार का बंटोधार कर दिया है।

राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम को लेकर

पटना एयरपोर्ट से रवाना हुई मेघालय पुलिस

पटना (एजेंसियां)।

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्यारोपी सोनम रघुवंशी को पुलिस ने पटना के फुलवारीशरीफ थाने में रखा था। इसके बाद पटना एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट से सोनम को लेकर रवाना हो गई। पुलिस टीम पहले कोलकाता पहुंचेगी फिर गुवाहाटी होते हुए शिलॉन्ग जाएगी।

बताया जा रहा है कि सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था। वहां से उसे पटना लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम को थाना परिसर स्थित अनुसंधान कक्ष में रखा गया है। यहां वह चुपचाप कुर्सी पर

बैठकर टेबल पर सिर रखकर सोती दिखी। सोनम पूरी तरह से खामोश है। न वह किसी से बात कर रही है।

थाना में मौजूद पुलिस अधिकारी ने उसे चाय और नारता भिजवाया, लेकिन उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया है।

इधर, सोनम की मौजूदगी की खबर मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना के बाहर मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है और किसी को भी अनुसंधान कक्ष या उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मेघालय से तीन पुलिसकर्मी और एक पुलिस पदाधिकारी के साथ

मेघालय पुलिस यूपी के गाजीपुर से पति की हत्या में गिरफ्तार पत्नी सोनम को लेकर परिवार से थाना पहुंची है।

इधर, सोनम को जिस कमरे में रखा गया है, वहां तीन महिला पुलिसकर्मी निगरानी में तैनात हैं। सूत्रों के अनुसार मेघालय पुलिस रास्ते में सोनम से कई बार पूछताछ की कोशिश कर चुकी है लेकिन उसने पूरी चुप्पी साध रखी है। फिलहाल सोनम के खिलाफ हत्या के साथ-साथ साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मेघालय पुलिस सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई है जहां आगे की पूछताछ होगी।

रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर बोला हमला

11 साल के कार्यकाल को लेकर निशाना साधा

पटना (एजेंसियां)।

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाद अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मोदी और नीतीश कुमार सरकार पर कई आरोप लगाए। सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए रोहिणी ने लिखा कि ‘कुर्सी पकड़ कुमार’ बेबस वब दिमागी रूप से लाचार हैं। पुलिस और सरकार अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है। अब केवल सुशासन का झूठा प्रचार कर रहा है। यह अपराध के बोलबाले वाला बिहार है। रोहिणी ने आगे लिखा कि



चहुंओर अपराध है। गोलियों की बौछार है। पुलिस से ज्यादा अपराधी वजनदार है। यही है नीतीशे कुमार जी के शासन में बिहार का सूरत-ए-हाल।

राजद नेत्री रोहिणी आचार्य ने

निकालते, पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियों को अपना बताते-बताते ही मोदी सरकार के 11 साल बीत गए। इन 11 सालों में कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसे यह सरकार बेमिसाल बता सके।

रोहिणी ने आरोप लगाया कि ‘देश की जमीन पर विदेशी अतिक्रमण, सीमा पार से धड़ड़े से घुसपैठ जारी है। अनवरत आतंकवाद का प्रहार है। कमरतोड़-बेलगाम महंगाई है। बेहिशाब बेरोजगारी है। डॉलर के मुकाबले दिन-ब-दिन कमजोर होता रुपया, देश पर विदेशी कर्ज का ऐतिहासिक बोझ है। गलत विदेश के कारण नीति से भारत

वैश्विक पटल पर अलग-थलग पड़ गया है। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में पिछले दो वर्षों से अराजकता कायम है। संवैधानिक संस्थाओं-व्यवस्थाओं पर कब्जे की कोशिशें, संविधान को बदलने की कुत्सित मंशा, विपक्ष के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का बेवजह इस्तेमाल, सैन्य-बलों के पराक्रम और सेना के अभियानों को अपना श्रेय बता चुनावी-राजनीतिक फायदा लेने की कवायदें। यही सब तो पिछले 11 सालों में देश को मोदी सरकार से मिला है। मगर बड़ी बेशर्मी से अपनी पीठ खुद ही थपथपाने का सिलसिला जारी है।

जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज में मरीज को

स्लाइन लगाते सुरक्षा गार्ड का वीडियो वायरल

मधेपुरा (एजेंसियां)।

मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। 800 करोड़ रुपये की लागत से बना यह मेडिकल कॉलेज शुरुआत से ही विवादों में रहा है। अब एक वायरल वीडियो ने इसकी लचर व्यवस्था को फिर से उजागर कर दिया है। इस बार मामला सर्जरी वार्ड का है, जहां मरीजों का इलाज प्रशिक्षित नर्सों के बजाय सुरक्षा गार्ड कर रहे हैं।

घटना चौथी बिल्डिंग के मेडिसीन वार्ड की है। जहां दो महिलाएं एक वृद्ध मरीज का इलाज कराने पहुंची थीं। मरीज की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात नर्स से संपर्क किया, लेकिन नर्स ने मरीज को देखने के बजाय एक सुरक्षा गार्ड को स्लाइन



लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी। गार्ड ने अनुभवहीनता के साथ स्लाइन लगाने की कोशिश की, लेकिन स्लाइन खुल गया और दवा बहने लगी। परिजनों की शिकायत पर गार्ड ने दोबारा स्लाइन लगाया, जो कई असफल प्रयासों के बाद सफल हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया।

मरीजों और परिजनों ने बताया कि वार्ड में

फाइल न मिलने की शिकायत सामने आई। परिजनों का कहना है कि उन्हें एक घंटे बाद आने को कहा गया, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। मेडिकल कॉलेज के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. अंजनी कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई है। सुरक्षा गार्ड को वार्ड से हटा दिया गया है और संबंधित स्टाफ नर्स से स्पष्टीकरण मांगकर विभाग को सूचित किया गया है।

थाने में तैनात एसआई पर भ्रष्टाचार का केस, डीजीपी के निर्देश पर कार्रवाई

दरभंगा (एजेंसियां)।

मधुबनी जिले के हरलाखी थाना में तैनात सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एसआई को एक केस के निपटारे के एवज में अपने सरकारी आवास पर रिश्तत लेते हुए देखा गया। हालांकि वीडियो की पुष्टि अमर उजाला नहीं करता, लेकिन इस क्लिप के वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और बिहार पुलिस के डीजीपी तक जा पहुंचा।

वीडियो के संज्ञान में आने पर डीजीपी ने मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद तत्काल



जांच कराई गई, जिसमें एसआई प्रमोद कुमार को दोषी पाया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उसी थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

हरलाखी थाना में इससे पहले भी कई पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता के आरोप में

कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। एसआई मनोज राम को रिश्तत लेते हुए वीडियो वायरल होने पर निलंबित किया गया था।

एसआई ध्यानी पासवान को एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड किया गया। पूर्व थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी को तस्करों से मिलीभगत के आरोप में निलंबित किया गया था। थाने के चौकीदार अजय कुमार का रिश्तत मांगने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उन्हें भी निलंबित किया गया। एसआई प्रमोद कुमार के

मामले में पहले पुलिस ने हरलाखी प्रखंड के पत्रकार हरि शम्भू को गिरफ्तार कर मामले को दबाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, तब जाकर कार्रवाई की दिशा बदली और सच्चाई उजागर हुई।

इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार पुलिस के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती से सामने रखा है। पहली बार मधुबनी जिले में किसी एसआई पर उसी थाने में केस दर्ज हुआ है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह स्पष्ट संकेत है कि अगर कोई भी कानून का रक्षक कानून तोड़ता, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है।